मध्यान भोजन : एक परिचय

कु. सांत्वना अग्रवाल
शोधकर्ता ग्रामीण विकास विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यंत जनोपयोगी योजना है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1955 को लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी, परिषदीय, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 03 किग्रा. गेहूँ अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बांटा जाता था, क्योंकि पूर्व में पके–पकाये भोजन की व्यवस्था नहीं था। इससे छात्र को वांछित पोष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर 2004 से पका–पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों मे उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007–2008 मे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 1.94 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका–पकाया भोजन विद्यालय मे दिया जाना प्रस्तावित है। 15 अगस्त 1995 में पहले देश के 2408 ब्लाकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997–98 के अंत तक NPNSPE को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया।

मध्यान्ह भोजन का उद्देश्य :–

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्द्ध प्राथमिक विद्यालयों ई.जी. एस.एवं ए.आई.ई. केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चों को पोष्टिक भोजन उपलब्ध करना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ना।
4. प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों में विद्यालय से रूकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाई–चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन करना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

केन्द्रीय सहायता के संघटक :– इस समय मध्यान्ह भोजन स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है–

1. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपर्ति केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।
2. 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात् अरूणांचल प्रदेश, असम, मेद्यालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और त्रिपुरा) के लिए दिनांक 01/12/2009 से इनमें प्रचलित पी.डी.सी. दरों के अनुसार परिवहन सहायता 1 अन्य राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए 75/– प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय खाद्य निगम से प्राथमिक स्कूल तथा खाद्यान्न के परिवहन में हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।
3. दिनांक 01/12/2009 से भोजन पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक प्रभार को छोड़कर) प्राथमिक बच्चों के लिए 2.50 रूपये की दर से और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 3.75 रूपये की दर से प्रदान की जाती है और दिनाक 01/04/2010 तथा दिनांक 01/04/2011 को इसे पुनः 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2016 से इन

दरों में फिर से परिवर्तन किया गया है और परिवर्तित दरें नीचे दी गई है। भोजन पकाने की लागत की केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य हिस्सेदारी 90:10 के आधार पर है और अन्य राज्यों/संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर वहन की जाएगी। तदनुसार केन्द्र की हिस्सेदारी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की न्यूनतम हिस्सेदारी वर्ष 2016–17 के लिए इस प्रकार है–

स्तर	प्रति भोजन कुल लागत	1 जुलाई 2016 प्रति बालक प्रति स्कूल खाने बनाने के खर्च गैर पूर्वोतर राज्य (60. 40)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10) केन्द्र राज्य
		केन्द्र	राज्य	
प्राथमिक	4.135	2.485	1.655	3.725 0.415
उच्च प्राथमिक	6.185	3.715	2.475	5.565 0.125

भोजन पकाने की लागत में दालों सब्जियों, भोजन पकाने के लिए तेल और मिर्च–मसालों, ईधन इत्यादि की लागत शामिल है।

4. पूरे देश में किचन–कम–स्टोर के निर्माण की प्रति विद्यालय 60,000 रूपये की एक समान दर के स्थान पर दिनांक 01/12/2009 से निर्माण लागत की कुरसी क्षेत्र मानदण्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्य अनुसूची दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। किचन–कम–स्टोर की निर्माण लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर की जाएगा। इस विभाग ने दिनांक 31/12/2009 के अपने पत्र 01/01/2009 + डेस्क (ए.डी.एम.) के जरिए 100 बच्चों तक स्कूलों में किचन–कम–स्टोर के निर्माण हेतु 20 वर्ग भी का क्षेत्र निर्धारित किया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों तक के लिए 4 वर्गमीटर अतिरिक्त कुरसी क्षेत्र जोड़ा जाएगा। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर 100 राज्यों के स्लैब को संशोधित करने का अधिकार होगा।

5. 5000 रूपये प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचिन के सामान में निम्नलिखित शामिल है– भोजन पकाने का सामान (स्टोव, चूल्हा, इत्यादि) खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।

6. दिनांक 01/12/2009 से रसोइयें–कम–सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय की 100 रूपये प्रतिमाह करना और 25 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक रसोइये–कम–सहायक, 26 से 100 विद्यार्थी वाले विद्यालयां में दो रसोइये–कम–सहायक और अतिरिक्त रसोइये–कम सहायक की नियुक्ति करना। रसोइये– कम सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के मध्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75:25 के आधार पर होगी।

7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम के प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) के लिए सहायता (क) खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (च) रसोइया–सह–सहायक को मानदेय के लिए कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत (क) खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया– सह–सहायक को मानदेय की कुल

सहायता तथा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

अद्यतन स्थिति :– गैर सरकारी संगठनों को (NGO) आउट सोर्स करना– शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहाँ गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/केन्द्रीकृत रसोइयों जो कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न है, के लिए रसोई–सह भंडार के लिए स्थान नहीं है। इस महत्वपूर्ण योजना में मिड डे मील की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को (NGO) आउट सोर्स किया गया है मिड डे मील के दिशा निर्देश पंचायतीराज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, माता संगठनों और स्थानीय समाज की सहायता से मिड डे मील को रसोइये–सह–सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई–सह–भंडार में पकाने पर जोर देते है। वर्तमान संगठन संलग्न है। इस कार्यक्रम में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 185 और 102 है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मिड डे मील दिशा निर्देश के अनुसार संलग्न गैर सरकारी संगठनों के मानदण्ड निम्न प्रकार है–

1. गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, वी.ई.सी/एस.एम.सी/पी.टी.ए., म्युनिसिपल कमेटी/कॉरपोरेशन आदि। एजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षो से अस्तित्व में होना चाहिए। इसके पास सामूचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढ़ांचा होना चाहिए, जिसके कार्यो और अधिकारों इसके संविधान से स्पष्ट उल्लेख हो।

2. गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय निकाय के मध्य होने वाले अनुबंध/समझौते में पक्षों का उत्तरदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होने चाहिए। बच्चों के लिए गैर–सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सरल व्यवस्था का होना भी इसमें शामिल होना चाहिए।

3. चयनित मिड डे मील आपूर्तिकर्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और कार्यक्रम अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।

4. इस प्रकार की मिड डे मील योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन योजना का नवीनीकरण :– बारहवीं योजना के दौरान माध्यान्ह भोजन योजना (MDMS) का निम्न प्रकार से सुधार करने का प्रस्ताव है–

1. मध्यान्ह भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार।

2. प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व–प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार। मौजूदा घटको ंया स्कूलो के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन।

3. उत्तर पूर्वी प्रदेश (NER) को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन इसका 75 रूपए प्रति क्विन्टल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 150 रूपया प्रति क्विन्टल की गई है।

4. वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान रसोइए सहायकों का मानदेय 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपया और वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान रसोइया–सहायक का मानदेय 2000 रूपये प्रति माह किया गया है।

5. खाद्यान्न लागत, खाना पकाने की लागत, माल वहन सहायता तथा रसोइया सहायक को मिलने वाले मानदेय के लिए कुल पुनरावर्ती केन्द्रीय सहायता के तीन प्रतिशत की दर से प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन दरों का संशोधन।

6. नए स्कूलों के लिए किचन की बर्तन खरीदने और हर पांच साल बाद किचन के बर्तनों को बदलने के लिए 15000 रूपये प्रति स्कूल की दर से केन्द्रीय सहायता की पद्धति का संशोधन/सहायता की यह राशि केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात से

और उत्तर –पूर्वी प्रदेश के राज्यों में 90:10 के अनुपात से वहन की जाएगी।

UNICEF, An Analysis of the Situation of children in India, Draft Report, 1981.

Food Aid to Education and Training, WFP, Rome, 1970.

Right to Adeqtiate Food as a Human Right, Centre for Human Rights, United Nations, New York, 1989.

The World Health Organisation, the United Nations, 1946.

UNDP, Human Development Report, 2005, New York.

UNICEF, Statistical Profile of Children and Youth in India, November 1975.

युवाओं के बदलते प्रतिमान

रजनीश बाजपेई
इन्दौर

प्रस्तावना :– भारत का युवा अब वैसा नहीं रहा जैसा कि वह दो दशक पहले हुआ करता था। हालांकि इससे पहले भी युवा ऐसा नहीं था कि उसे आदर्श कहा जाए फिर भी भारतीय होने की भोली–भाली गंध उसमें अवश्य थी। उस समय हम ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से भारत के भारत बनने की संभावनाएं अब से कहीं ज्यादा थीं। इससे पहले इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि राजाओं के आपसी वैमनस्य और विदेशी शासकों के कारण यह देश अपने सामूहिक उद्देश्य को लेकर आगे नहीं बढ़ सका, जिसके लिए इस भारत भूमि का धरा पर अस्तित्व था। हम स्वतंत्रता के साथ उगे नए सूरज की अगवानी करने में असमर्थ रहे। अंग्रेज हमें दोयम दर्जे का अंग्रेज बनाकर चले गए। वैश्वीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों ने रही सही कसर पूरी कर दी। इसने भारतीय समाज व्यवस्था की नींव को हिलाकर कर रख दिया। समय के साथ समायोजन का प्रयास करता भारतीय समाज वैश्वीकरण और इससे उत्पन्न अनेक दुख–सुख अपनी छाती में समाए हैं। पर इसके दुष्परिणाम ही ज्यादा कहे जा सकते हैं क्योंकि वैश्वीकरण ने एकाकी संस्कृति को विकसित किया जिसके साथ भारत की भाईचारे की उत्सवपूर्ण संवेदनात्मक संस्कृति को धक्का लगा।

छुईमुई भारतीय स्त्रियों की जगह स्वयं को पुरूष से किसी भी मामले में कम न मानती हुई मर्दनुमा औरतों ने ले ली जिन्होंने स्त्री होने के अर्थ को कभी समझा ही नहीं बल्कि स्त्री की छवि उनके मन में दबी–कुचली दीन–हीन अबला की बनी रही। उनके तर्को से एक ही बात निकली कि भारतीय संस्कृति ने स्त्री को सिर्फ छला ही है। वह स्त्रीत्व के उस मान को नहीं समझ सकीं। पुरूष तो सदैव बचकाना है जबकि स्त्री के उपर इसे सही राह दिखाने की जवाबदारी हमेशा इस संस्कृति का हिस्सा रही है। ऐसे अनेक इतिहास पुरूषों से जिन्होंने इस धरा को अपने अहं प्रदर्शन का रंगमंच बना लिया, उनकी स्त्रियों के गरिमापूर्ण आख्यानों से भारतीय संस्कृति का इतिहास भरा पड़ा है। नारी की गरिमा सदैव पुरूषों से उपर रही है क्योंकि पुरूषार्थ कितना भी समर्थशाली हो, जन्म किसी स्त्री की कोख से ही लेता है। काश ! अपनी उस गरिमा को नारी फिर से समझ सके और पुरूषों से होड़ न कर अपनी स्वयं की स्वतंत्र गरिमा और अस्तित्व को पहचाने जिसे मापने का पैमाना किसी भी हालात में पुरूष नहीं हो सकता। वैश्वीकरण की आंधी ने भारत का जो नुकसान किया है उसमें एक बड़ा नुकसान यह भी है कि हम बेसहारा हो गए। सभी के लिए विश्रामस्थली और जीवन को समझने के स्थल के रूप में मशहूर रही परिवार संस्था ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। पुरूषों के आदर्शो पर चलती वैश्विक स्त्री परिवार के आदर्श ठुकरा रही है। भारतीय संस्कृति की आत्मनिर्भर परिवार और कुटुम्बों की अवधारणा संयुक्त परिवार के समापन की प्रक्रिया के साथ विलोपित हो रही है। संयुक्त परिवार में बेपरवाह रहने वाला युवा आज अपने सारे जीवन की जवाबदारी स्वयं के मासूम कंधों पर महसूस कर उसके बोझ से दबा जा रहा है। उसकी हंसी खो गई है। अत्याधिक तनावयुक्त वातावरण में नई वैश्विक बीमारियां सामने आ रही हैं जिनमें डिप्रेंशन तो आज एक वैश्विक समस्या है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या जैसे घातक कदम तक उठा लेता है। व्यक्ति तो बिल्कुल एकाकी हो गया लेकिन अपनी हर आवश्यकता के लिए बाजार पर निर्भर हो गया। एक परावलम्बन की संस्कृति इसी वैश्वीकरण की वजह से पनपी। अमेरिका में हो रहे परिवर्तन भारतीयों को भी प्रभावित करने लगे।

बदले प्रतिमान :– पहले भारत गांवों का देश था और हर गांव अपने आप में स्वतंत्र राज्य था। आज विकसित होती महानगर संस्कृति में आदमी भले ही अकेला है पर अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर है। जीवन कितना विविध होता है काश ! इसको हम इसकी संपूर्णता में स्वीकार कर सकने का साहस कर पाते। इसे हमेशा समय की ही विडम्बना कहेंगे कि हम किसी भी स्वरूप के या तो सकारात्मक पक्ष ही देखते हैं या नकारात्मक। जबकि जीवन ऐसा नहीं है। जीवन तो पूरा है जिसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों समाई है। जीवन विज्ञान का खोजने का जिम्मा इस देश के उपर

था जिसके क्रम को आगे बढ़ाने की जवाबदारी इस युग पर थी। पर चमत्कार को नमस्कार के चक्कर में जीवन के असली अर्थ ही खो गए। हवा में उड़ते हवाईजहाजों और खड़–खड़कर बिना किसी मानवीय सहायता के रूपया गिनती एटीएम मशीनों ने युवा पीढ़ी को विस्मृत कर दिया। हम मुरीद हो गए उनके जिन्होंने इनकी रचना की थी। निश्चित रूप से यह चमत्कारिक था लेकिन इससे ज्यादा चमत्कारिक नहीं कि सूरज कैसे अपने समय पर रोज आ जाता है, जिन्दगी भर हाय–हाय मचाने वाला मनुष्य मरने के बाद आखिर कहां चला जाता हैं। इस देश की कथाएं जीवनपार अलौकिक बातों से भरी हुई है। मानवता के चरम आश्चर्य इसी देश में घटे। लेकिन इस तल पर हमारी युवा पीढ़ी कोई चमत्कार नहीं देख सकी। वे युवा जो भारत की ऋषि परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे वे पश्चिम के विलासितापूर्ण जीवन को अपना आदर्श बना बैठे। वे युवा जो ऋषि हो सकते थे, शराब के नशे में चूर सड़क दुर्घटनाओं में अपना अनमोल जीवन गंवाने लगे। दूसरों की बनाई गाड़ियों की तेजगति में युवा अपनी महानता के किस्से गढ़ने की कोशिश करने लगा।

युवा किसी भी राष्ट्र के कर्णधार हैं, उसके भावी निर्माता हैं। आने वाले समय में युवा अपनी विविध भूमिकाओं से रा''ट्र को प्रभावित करते हैं। शिक्षक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, साहित्यकार, कलाकार और शासक–प्रशासक रहते हुए वह देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए उनके उपर अपनी सम्यता, कला एवम् ज्ञान की परम्पराओं को मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे ले जाने का गहरा दायित्व होता है। पर इसके विपरीत यही युवावर्ग उन परंपरागत विरासतों का वाहक बनने से इंकार कर दे तो निश्चित ही किसी राष्ट्र का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। युवा शक्ति जब तक सकारात्मक रूप में है तो सही है, पर नकारात्मक स्वरूप में विध्वंसात्मक बन जाती है। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर क्यों युवाशक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जिसके लिए अकेले युवा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। युवाओं में नकारात्मक बदलावों के लिए व्यवस्था द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं जो युवाओं में उचित–अनुचित का विवेक तक उत्पन्न नहीं कर पा रही है। कुछ विद्वानों के अनुसार 30 वर्ष की उम्र तक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अस्थिर होता है। वह कई तरह के दबावों, संकटों, संभावनाओं, आकांक्षाओं और प्रेरणाओं के बीच से गुजरता हुआ अपने चित्त में स्थिर होने की कोशिश करता है। इस अवस्था में युवाओं को संभालना किसी राष्ट्र का कर्तव्य होता है तभी युवा उसके नाम, उसके आदर्शो और उसकी विरासतों को आगे ले जाने की अपनी जवाबदारी को समझने में सक्षम हो पाते है।

भारत में अभिवादन का महत्व रहा है। वाकई में अभिवादन की जैसी परंपरा हमारे देश में रही है वैसी परंपरा या संस्कृति दुनिया के किसी भी देश में नजर नहीं आती। अपनों की या अपने जानने–पहिचानने वालों की तो छोड़िए, किसी अजनबी के प्रति भी परमात्मा सी श्रद्धा इस देश की हवाओं में व्याप्त थी। आज भी गांवों या सुदूर अंचलों में यह परिपाटी व्याप्त है। लोग अपनी–अपनी बोलियों, भाषाओं और रीति–रिवाजों के अनुसार मिलने–जुलने वालों का अभिवादन करते हैं। 'जय रामजी' जैसे जुमले आज भी यदा–कदा सुनने को मिल जाते है लेकिन आधुनिक संस्कृति की बदलाव की बहती बयार ने हमारी इस गौरवशाली परंपरा को भी कहीं गहरे तक प्रभावित कर दिया है।

'प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। मात–पिता गुरू नावहिं माथा।।' तुलसी की ये चौपाई जो कभी भारतीय युवाओं के सुबह उठते ही व्यवहार तय करने के पैमाना थी। आधुनिक युग में पैमाना पुराना पड़ चुका है। भले ही वैश्वीकरण के पहले के युवा भी ऐसा कम ही करते रहे हों पर ये बातें भारतीय परिवारों की शिक्षा का विषय होती थीं। गुरूओं, बुजुर्गो और पारिवारिक प्रतिमानों में भी बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं। भले ही बदलाव प्रतिशत में कम हों पर युवाओं का रूझान स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भविष्य इन्हीं बदलावों का साथ देगा। बुजुर्गो से मिलकर उनके चरणस्पर्श करने वालों का प्रतिशत 42 है पर इस पीढ़ी के साथ यह पूरी तरह समाप्त हो सकता है क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासतें अब शिक्षा और संस्कार का विषय नहीं है।

पुराने भारतीयों के जीवन में सुबह से ही स्नान पूजन की जो महत्ता रही है अब नहीं रही। आज का 90 प्रतिशत युवा यह स्वीकार कर रहा है कि सुबह उठकर अपनी दयनंदिनी में योग और स्नान पूजन शामिल करना आज उसके बस की नहीं है।

40 प्रतिशत युवा गणतंत्र दिवस को साधारण अवकाश की तरह मानते है। मात्र 40 प्रतिशत युवा ही

इस दिन स्वयं में कुछ स्पंदन सा महसूस करते है और राष्ट्रीय धर्म को निभाते हुए किसी समारोह के माध्यम से इस पर्व की खुशी मनाते हुए शहीदों के प्रति श्रद्धांजली व्यक्त करते हैं। भगतसिंह जैसे वीरों को उनके जन्मदिन के अवसरों पर भी याद नहीं किया जाता। राष्ट्र के असली हीरो शहीदों को विस्मृत कर हम पर्दे के अभिनेताओं को हीरो मान बैठे हैं। उसी का असर वैश्वीकरण के बाजार पर दिख रहा है मीडिया रोज ये भारी भरकम जगह घेरते हैं। क्या सोचते हैं युवा, अतिथियों के विषय में सार्वजनिक स्थलों पर प्रेम के इजहार के विषय में युवाओं की नजर में शिक्षा के मायने के मायने क्या हैं? गुरूः विष्णु गुरूः देवो महेश्वरः के देश में अब एक अलग संस्कृति पसार रही है। गुरू के सम्मान की घटती प्रवृत्ति का ही संकेत है कि आज उन्हें पैसे के लिए कार्य करने वाला एक साधारण व्यक्ति माना जाने जगा है। 10 प्रतिशत युवाओं ने ऐसी ही राय दी। 12 प्रतिशत ने गुरू को एक मित्र से अधिक दर्जा देने से इंकार कर दिया। हालांकि 62 प्रतिशत के लिए अभी भी गुरू ब्रह्म है पर इतना कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की हवा ने शिक्षातंत्र को बुरी तरह हिला दिया है।

अर्थ के, राजनीति, भारत, साम्प्रदायिकता, मीडिया, भारत की वर्तमान नीतियों, भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म, रामसेतु, वृद्धों के और भारत के अनाक्रमण संबंधी इतिहास के विषय में युवा क्या सोचता है ? सामान्य जनजीवन में युवाओं का निजी व्यवहार पहले के युवाओं से बिल्कुल बदला हुआ है, युवाओं के बीच शराब एक आम चलन में शामिल हो चुकी है। द इंडियन एंटी एल्काइन सोसायटी के सहयोग से एचोसेम ने दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई, पटना, पुणे, हैदराबाद, बंगलुरू, कोचीन, चंडीगढ़ में तीन हजार छात्रों के सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष बताया। रिपोर्ट के अनुसार अब महिलाएं भी शराब की लत की चपेट में है। युवा लड़के सप्ताह में औसतन 12 पैग या छह बीयर के बराबर मदिरा का सेवन कर रहे हैं। अन्य शहरों की अपेक्षा दिल्ली के युवा शराब पीने के मामले में युवा 20 फीसदी आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण युवा अपनी आय का 26 प्रतिशत जबकि शहरी युवा अपनी आय का 38 प्रतिशत शराब में खर्च कर रहा है। युवाओं के निजी जीवन में सब कुछ बदल रहा है, सप्ताहांत, जन्मदिन, सांस्कृतिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार मनाने के ढंग बदल चुके है।

मूल बदलावों के प्रमुख बिन्दु

युवाओं के व्यवहारिक तरीकों में आए बदलाव

अभिवादन – माता पिता से। बुजुर्गो से।
दिनचर्या – सुबह उठने का समय। रात में सोने का समय। सुबह उठकर पहली पसंद। स्नान। सप्ताहांत पर युवाओं का पसंदीदा व्यवहार। जन्मदिन मनाने का तरीका। सांस्कृतिक त्यौहारों के प्रति युवाओं का व्यवहार। राष्ट्रीय त्यौहारों के प्रति युवाओं का दृष्टिकोण।

क्या सोचते हैं युवा

- अतिथियों के विषय में।
- सार्वजनिक स्थलों पर प्रेम के इजहार के विषय में।
- युवाओं की नजर में शिक्षा के मायने।
- गुरूओं के विषय में।
- अर्थ के विषय में।
- राजनीति के विषय में।
- साम्प्रदायिकता के विषय में।
- मीडिया के विषय में।
- भारत की वर्तमान नीतियों के विषय में।
- भारतीय संस्कृति के विषय में।
- पुनर्जन्म के विषय में।
- रामसेतु के विषय में।
- अवतारवाद के विषय में।
- वृद्धों के विषय में।
- भारत के अनाक्रमण संबंधी इतिहास के विषय में।

संदर्भ :–

1. देसाई, बी.जी., 1964, द इमिर्जिंग यूथ. बॉम्बे : पापुलर प्रकाशन
2. दुर्खीम, ई. 1983, प्रोफेशनल इथिक एण्ड सिविक मोरल्स, न्यूयार्क : फ्री प्रेस
3. गुडे एण्ड हॉट, 1952, मेथड इन सोशल रिसर्च टोक्यो : मैक ग्रा हिल कॉ.
4. गोर, एम.एस., 1977 इण्डियन यूथ : प्रॉसिस ऑफ सोशलाईजेशन न्यू देहली : विश्व युवक केन्द्र
5. गोर, एम.एस., 1982, एजुकेशन एण्ड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

महिलाओं से संबंधित मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाएं

डॉ. सुमन तिवारी
राजनीति शास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

प्रस्तावना : महिलाओं की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय उनके लिए सेवा योजना के अवसर उत्पन्न करना था। इस बात का प्रयास किया गया कि उनको जनता वितरण व्यवसाी, ग्रामीण गोदामों, बाढ़ नियन्त्रण, डेयरी विकास और सामाजिक वानकी आदि में नौकरियाँ मिलें। इसी प्रकार पारम्परिक व्यवसायों को आधुनिक बनाकर जैसे सूत कातना और कपड़ा बुनना, दिया सलाई बनाना, दरी कालीन बनाना, कृषि मछली पालन आदि में कुशलता की वृद्धि के साथ उनको वैकल्पिक सेवा नियोजन प्रदान करना था। महिला सेवास नियोजन के विकास के लिए प्राप्त विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की गई। ग्रामीण युवक स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण ;ज्त्ल्म्डद्ध के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

शिक्षा, स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन और सेवायोजन से सम्बन्धित कार्यक्रम स्त्रियों की सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने में बहुत सहायक हुए। तथापि स्त्रियों के आर्थिक उच्च स्तर का विकास देश में व्याप्त सामाजिक मूल्य व्यवसाी, दृष्टिकोण और सामाजिक संरचना के परिवर्तन पर निर्भर था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1986–90) – सातवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं में विश्वास का भाव जगाने उनके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रति चेतना जगाने और आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रति संकेत किया। योजना में महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) – इस योजना में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक गारन्टी और विशेष कानून होते हुए भी अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान न होने के कारण स्त्रियाँ लगातार कष्ट भाग रही हैं इसके अतिरिक्त स्त्रियों को उनके अधिकार देने के प्रति सामाजिक विरोध, वैधानिक सुविधाओं की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की ऐसी संस्थाओं को कभी जो उनके हितों की रक्षा कर सके, के कारण भी स्त्रियों को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। दहेज निरोधक अधिनियम के बनने और कानून तोड़ने पर सख्त सजा होते हुए भी दहेज की यह कुप्रथा लगातार चली आ रही है। स्त्रियों के विरूद्ध अपराध जिसमें घरेलू दायरा भी शामिल है उनके अस्तित्व को बलात्कार दहेज सम्बन्धी अत्याचार और हत्या के मामलों से कुंठित किया जा रहा है।

इस योजना की यह नीति थी कि विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों से महिलाओं को वंचित न किया जाए और सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाए। स्त्रियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लाभ मिलने चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के उत्पादक समूह और सहकारी समितियां बनाने की आवश्यकता रही। जिला संघ और महिलाओं की समितियों को ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए और उन्हें तकनीकी सहायता, ऋण और अपने उत्पादन को बेचने की सुविधाएँ देने के लिए प्रोत्साहित करना था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) – नौवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के एजेन्ट के रूप में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की वचनबद्धता दर्शायी गई थी। महिलाओं एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस दिशा में अनेक कदम उठाये गए। उनमें से कुछ निम्न लिखित है ।

1) **ग्रामीण महिलाओं का विकास और अधिकारिता (स्वशक्ति) परियोजना** – केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में इसे 16 अक्टूबर, 1998 को पाँच वर्ष के लिए मंजूर किया गया तथा इसके लिए 186.21 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए एक उपयुक्त पर्यावरण निर्मित करना था। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और बिहार के 35 जिलों में यह परियोजना चलाई जा रही है।

2) **स्वयंसिद्धास योजना** – स्वयंसिद्धा योजना मार्च 2001 में शुरू की गई। यह इन्दिरा महिला योजना का ही परिष्कृत रूप है जिसमें महिला अधिकारिता कार्यक्रम शामिल कर दिया गया है और

वर्तमान में 238 ब्लाकों में चल रहे इस कार्यक्रम का दसवीं योजना के अन्त तक 650 ब्लाकों में विस्तार कर दिया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है :–

- आत्मनिर्भर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाना।
- इन समूहों के सदस्यों में विश्वास और जागरूकता उत्पन्न करना, आर्थिक संसाधनों पर उनका नियन्त्रण, लघु ऋणों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना।
- स्थानीय स्तर की योजना में महिलाओं की भागीदारी और महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों के संवाओं को समान रूप देना।

राज्य सरकार इस योजना को राज्य स्वर पर पहचान किये गए प्रमुख विभागों और लागू करने वाली ब्लाक स्तरीय एजेंसियों के जरिए लागू करेगी।

3) **महिला समृद्धि योजना** – देश की ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालने के उद्देश्य से सन् 1993 में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी। अब यह योजना इन्दिरा महिला योजना में सम्मिलित कर दी गई है।

4) **महिला के सशक्तिकरण के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम** – इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी और भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान के सहयोग से कल्याण मन्त्रालय ने जमीनी स्तर अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए ऐसी कार्य योजना तैयार की है, जो महिलाओं को गतिमान और सशक्त बनाने के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है। इस दिशा में परियोजना की प्रारम्भिक गतिविधियाँ पूरी हो चुकी है और जुलाई 2000 से ऐसा पहला कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है।

5) **आयोग राष्ट्रीय महिला** – राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया था। आयोग को सौपे गए कार्य व्यापक और विभिन्न प्रकार के हैं, जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी उन्नति को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी मुद्दों के लगभग सभी पहलुओं से जुड़े हुए है। आयोग ने महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य के लिए आयोग पारिवारिक महिला लोक अदालतें लगाने, पारिवारिक विवादों में परामर्श सेवाएँ देने तथा महिलाओं में कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

6) **महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति** – सितम्बर, 1995 के दौरान बीजिंग में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में भारत द्वारा किए गए वायदे के मध्य नजर भारत सरकार ने विश्व स्तर पर महिलाओं के स्तर की जानकारी लेने के बाद भारत में भी महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के समान संवैधानिक दर्जा दिया है। बिना किसी भेदभाव के महिला पुरूष एक समान माने गए है। सभी प्रकार के सलाह मशवरे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस नीति के अनुसार कार्यवाही जारी है।

7) **राष्ट्रीय महिल संसाधन केन्द्र** – महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र गठित करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उन्हें समुचित जानकारी उपलब्ध कराना, शोध और उन्हें दस्तावेज तैयार करने जैसी सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र एक केन्द्रीय निकाय होगा, जो नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग भेद मामलों पर नीति परक फैसले लेगा।

नौवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को विशेष प्राथमिकता पर रखा गया। इस दिशा में उन क्षेत्रों को पहचान पहले से ही कर ली गई थी, जहाँ विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे कम साक्षरता वाले क्षेत्र हैं – सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाएँ और बालिकायें जैसे– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियाँ, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि। कुल जनसंख्या में इन वर्गो का साक्षरता का प्रतिशत 5 से 10 प्रतिशत के बीच है जबकि 2011 की जनगणना में औसत राष्ट्रीय महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) – 21 दिसम्बर 2002 को राष्ट्रीय विकास परिसर द्वारा अनुमोदित दसवी पंचवर्षीय योजना 2002–07 को 1 अप्रैल 2002 से लागू किया गया। यह योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हुई इसमें मातृत्व मृत्यु दर को सन् 2007 तक 2 तथा सन् 2002 तक 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक कम करना। साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगात्मक अन्तर को सन् 2007 तक 50 प्रतिशत करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) – भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। 2007–12 की अवधि वाली इस योजना के प्रारूप को योजना आयोग ने 8 नवम्बर 2007 को व केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने 20 नवम्बर 2007 को मंजूरी प्रदान की थी। इसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर सुदृढ बनाना है।

- 0–6 आयु वर्ग के लिंगानुपात को वर्ष 2011–12 तक बढ़ाकर 938 तथा 2016–17 तक 950 करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा 33 प्रतिशत हो।
- यह सुनिश्चित करना कि काम करने की किसी बाध्यता के बिना सभी बच्चे सुरक्षित बाल्यावस्था का आनंद उठा सके।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) – वर्तमान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना का संचालन किया जा रहा है। बारहवीं योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए है और लक्ष्यों को पूर्ण करने से सम्बन्धित नीतियों का निर्माण कर संचालन किया जा रहा है।

इस प्रकार महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा हेतु सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं ये प्रयास पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर किये जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं का विकास सम्भव हो सका है। आज महिला प्रत्येक क्षेत्र में न सिर्फ कार्य कर रही है बल्कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

गजेटियर ऑफ इण्डिया भोपाल 2007.

मध्यप्रदेश पंचायिका : मार्च 2013, मई 2010, अक्टूबर 2012.

डॉ. राव : मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास, साहित्य भवन पब्लिकेशन।

योजना 2006, 2009, मई 2000

अग्रवाल, जे.सी.: भारत में नारी शिक्षा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।

कुरूक्षेत्र, मई 2000: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

D.M. Chaudhary: The Hindu Section Act, p.10711

Hindu marriage Act, 19

डॉ. फड़िया बी.एल. लोक प्रशासन साहित्य भवन, पब्लिकेशन।

डॉ. जी.आर. मदन : समाज कार्य विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली–7

श्रीवास्तव, सुधारानी 1999: भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था

डॉ. सपना शर्मा

श्रुति जैन

सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, माता गुजरी, महिला महाविधालय, मठाताल, जबलपुर म.प्र
शोध छात्रा, वाणिज्य, रानी दुर्गावती विश्वविधालय जबलपुर म,प्र

शोध सार : प्राचीन काल से ही पंचायतें हमारी सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था का अंग रही हैं। 1992 में संसद ने स्वावलम्बन और सामनता के उददेश्य से संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को सवैंधानिक हैसियत प्रदान कर सत्ता में आम आदमी की भागीदारी का रास्ता खोला। सत्ता की विकेन्द्रीकरण का यह प्रक्रिया पंचायती राज के निरन्तर विकास का परिणाम है। पंचायत व्यवस्था का उदभव कब हुआ तथा इसका तत्कालीन स्वरूप क्या था। यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि जब मानव समाज का उदय हुआ लगभग उसी समय से पंचायती राज व्यवस्था का भी उदय हुआ। पॉच व्यक्तियों की सभा एक प्राचीन संस्था हैं जिसका अस्तित्व अनेक राजनैतिक एवम् आर्थिक परिर्वतनों के पश्चात बना रहा हैं। पंचायती राज –ऐसी क्रान्ति है जो लोकतन्त्र को करोडों भारतीयों के द्वार तक ले जाएगी। यह एक ऐसी क्रान्ति हैं जो विकास की ज्योति को हमारे लाखों ग्रामों तक पॅहुचाएगी। यह ऐसी क्रान्ति हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाखो लोगों और हमारे देश की आधी जनसंख्या अर्थात् भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए नए अवसरो के द्वार खोल देती हैं।

मुख्य की वर्ड ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था

गांव–पंचायत की बेहतरी हेतु शासकीय पहल पर पंचायत राज की व्यवस्था पर आधारित हैं पंचायत समिती को सरकार या सरकार एजेन्सियों के अत्यधिक नियन्त्रण में जकडा नही जाना चाहिए, उसे गलतिया करने और उन गलतियों से सीखने की क्षमता दी जानी चाहिए लेकिन साथ ही उसे पथ प्रर्दशन की आवश्यकता होगी, सरकार को चाहिए की वह उसे समुचित पथ प्रर्दशन प्रदान करे जिससे वह गलतियों सं बच सके।

विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक –सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ हैं। सह पूछिए तो नए भारत के नए बाजार के केन्द्रं बनते जरा रहे हैं और यह सम्भव हो पाया है जब पंचायत के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाओं सीधे–सीधे गाांव और ग्रामीणों से जुड़ रही हैं अब सरकार की कोशिश इन संस्थाओं को ज्यादा अधिकार देना ही नही ,बल्कि वि्तिय रूप से मजबूत बनाना और बेहतर कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करना हैं। ताकि देश के आर्थिक विकास गांव में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सके। गांवो का विकास तभी संम्भव हो सकता हैं जब विकास का ताना बाना और नितियों के अमल की रूपरेखा तैयार की जाए। कुछ इसी तरह की सोच योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी भारत के राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान के गठन के समय भी आई जब दिल्ली से सुदूर गांवो पर नीति थोपे जाने के बजाए वहां से नीतियों को लेकर सोच लाने की बात कही गई। तकनीकी भाषा में आप कह सकते हैं ऐसी ही व्यवस्था पंचायती राज व्यवसथा के महत्व को और बढाती हैं। ग्राम पंचायत, जिसे आप लोकतंत्र की पहला कडी कह सकते हैं, सीधे–सीधे उन लोगो से बनी और उन लोगो से जुडी हैं जिनके लिए कवकास की पीतिंया बनायी जानी हैं। ऐसे में यदि इस तरह की संस्था विकास का आधार करे तो निश्चित तौर पर वह ज्यादा व्यवहारिक होगा। कुछ इसी सोच के साथ संविधान में 73वां संशोधन कर देश मे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था हैं जिसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत केवल उन्हीं राज्यों में जहां आबादी 20 लाख से अधिक हो दौर जिला पंचायत की बात कही गई। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई हैं। पंचायत राज मंत्रालय के ताजा आकडें बताते हैं कि देशभर में इस समय 608 जिला पंचायत, 6568 मध्यवर्ती पंचायत और 2,47,934 ग्राम पंचायत हैं।

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता हैं **क,** केंद्रीय योजनाओं को लागू करना **ख**, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नई योजना तैयार करना और उन पर अमल करना। केंद्रीय योजनाओं की सुची में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, कौशल विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना और इंदिरा आवास

योजना के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम,ज्योती योजना, स्वच्छ भारत अभियान और सांसद आर्दश ग्राम योजना को भी शामिल किया गया हैं। वैसे तो ये योजनाए अलग–अलग मंत्रालयो की हैं लेकिन उनके बेहतर नतीजे तभी इेखने को मिल सकते हैं जब ग्राम पंचायत अहम भूमिका निभाए।

मनरेगा – एक कानून के तहत भुरू की गई रोजगार गांरटी की यह योजना 73वें संविधान संशोधन के लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे अह माध्यम तो हैं ही, साथ ही पंचयात राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने का जरिया भी। वैसे तो यह योजाना ग्रामीण योजना के तहत आती है लेकिन इस कानून में साफ तौर पर पंचायत के तीनो स्तर को योजना का खाका खींचने से लेकर उन पर अमल करने का काम सौंपा गया। इस काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम किया गया।

- काम के इच्छुक लोगो से पंजीकरण के लिए आवेदन लेना, जावं व पहचान करना, पंजीकरण करना, जाबॅ कार्ड जारी करना और आवेदन जमा करने के 15 दिनो के भीतर काम मुहैया करना।
- समय–समय पर सर्वेक्षण के जरिए ये जानने की कोशिश करना कि खास इलाके मे किस तरह काम की जरूरत हैं फिर काम की पहचान कर योजना तैयार कर मंजूरी के लिए भेजना।
- सालाना आधार पर योजना के तथ्यो और कामयाबी की रपट तैयार करना। योजना की पहचान और अमल में ग्राम पंचायत की मदद ग्राम सभा करती है। यही नही योजना का सामाजिक अंकेक्षण भी ग्राम सभा में होता हैं। जहां आम लोग एंजेंसियों से योजना के कामकाज को लेकर सीधे–सीधे जबाव–तलब कर सकते हैं। इसी तरह मध्यवर्ती पंचायत को प्रखडं –स्तर और जिला पंचायत को जिला–स्तर पर रोजगार गांरटी योजना के अमल का जिम्मा है। इस योजना के भुरू होने से लेकर तीन लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का खर्च हो चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन – ग्रामीण के विकास के इस अहम अभियान के तहत, सरकार 2021–22 तक करीब 10 करोड गरीब ग्रामीण परिवारों को जीविका के लिए जरूरी साधन मुहैया कराना चाहती हैं। ध्यान रहे कि सामाजिक आर्थिक और धर्म आधारित 2011 की जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में 10,71 करोड परिवारों वंचितों की श्रेणी में आते है। जिन्हे दो जून की रोटी या सिर पर छत नही मिलती। ऐसे परिवारो को ध्यान मे रखकर तैयार किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन की खास विशेषता पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल हैं।

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो और उनमें से भी सबसे ज्यादा गरीब और बेहद कमजोर की पहचान करना और उन्हें स्वसहायता समूहो के साथ संगठित करना।
- स्वसहायता समूह को काम के लिए वित्तीय संसधान और बुनियादी सुविधाएं मुहैया करना।

इस मिशन की शुरूआत जून 2011 में की गई और ये अभी गोवा को छोड कर सभी राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उपलब्ध हैं। इसका मकसद प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्व–सहायता समूह में लाना हैं। ये कम चरणबद्ध तरीके से 2024–25 तक वूरा किया जाना हैं। अजिविका कि सहायता से लगभग 1,58 लाख युवाओ ने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं। 24,5 लाख महिला किसानो को भी सहायता दी गई हैं। बदलते वक्त की जरूरत के मद्देनजर मिशन के तहत कुछ खास पयिोजनाएं शुरू की गई हैं। मसलन, गावं की गरीब कन्याओ और महिलाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देकर शहर ले जाने और उनके साथ गलत व्यवहार को रोकने के लिए कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड मे पायलट प्रोजेक्ट के तहत मैला उठाने वाले लोगो के पुनर्वास और आंध्र प्रदेश में गरीब विकलांगों को जीविका का साधन मुहैया कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका हैं। अब तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडू और झारखंड में गरीब ग्रामीण परिवार के बुजुर्गो के लिए स्व– सहायता समूह के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी है।

इंदिरा आवास योजना – सर पर छत की चाहत को पूरा करना आसान नही होता और खासतौर पर जब ग्रामीण गरीबों की बात की जाए तो ये मुश्किल और भी बढ जाती हैं। कुछ इसी को ध्यान में रखकर इंदिरा आवास योजना की अवधारणा तैयार की गई। जिसमें घर बनाने मे सरकार मदद करती हैं। वैसे तो योजना में पंचायमी संस्थाएं और जिला ग्रामीण विकास संस्थाएं

मिलकर तय करती हैं कि एक पंचायत में कितने घर बनेगेंया कितने का सुधार होना हैं लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी ग्रामसभा की होती हैं।

- लक्ष्य की जानकारी ग्राम पंचायत को दी जायगी। इसके आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो में से इंदिरा आवास योजना के प्रतिक्षार्थीयों की सूची से लाभार्थी चुने जाएंगे।
- ग्राम पंचायत बगैर घर वाले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाल परिवारो की सूची से लाभार्थी चुने सकते हैं।
- लेकिन परिवारो के चयन को लेकर ग्राम सभा का फैसला अंतिम होगा इस पर किसी और की मंजूरी की जरूरत नही होना चाहिए।

सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के मुताबिक ग्रामीण इलाके में 17,94 करोड परिवार ऐसे हैं जो एक या एक कमरे, कच्ची दीवार या कच्ची छत वालो घर में रहते हैं। यहां कुल मिलाकर गांवो में रहने वाले 10 करोड से ज्यादा ऐसे परिवारो की पहचान की गई। जिनके पास या तो घर नही हैं, भीख मांगकर जीते हैं। मैला ढोते हैं, आदिम जनजाति हैं फिर कानूनी तरीके से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हैं। इंदिरा आवास योजना के जरिए ऐसे लोगो को घर बनाने मे मदद करता हैं। योजना के तहत विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशो, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर के मैदानी इलाको में गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को 70 हजार रूपये और पहाडी इलाको में 75 हजार रूपये की मदद दी जाती हैं। इसके अलावा कच्चे घर को पक्के में तब्दील करने के लिए 15 हजार की मदद का प्रावधान हैं।

हालांकि निर्माण सामग्री की लागत और मजदूर की दरो में बढ़ोत्तरी को देखते हुए ये रकम काफी कम हैं। इसके साथ ही 2022 तक सभी पक्के घर के लिए मुहिम के मद्देनजर सरकार सहायता राशि बढाने पर विचार कर रही हैं। साथ ही योजना के नए स्वरूप में लाभार्थी के लिए हर घर में शौचालय जरूरी होगाा। दूसरी ओर, सहायता मिलने के 2 वर्ष के भीतर घर बनाने की शर्त कई गरीब परिवार पूरा नहीं कर पाते क्योकि बाकी रकम जुटाना उनके लिए मुश्किल होता हैं। इसके लिए सरकार की कोशिश हैं कि देरी नजर रखी जायेगी।

संदर्भ स्रोत –

पत्र सूचना कार्यालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट
पंचायती राज मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट
कुरूक्षेत्र

Women empowerment in india : issues and solution

Dr. Sulekha Mishra
Professor Political Science
Govt. MKB Arts and Commerce Autonomous College for Women Jabalpur (M.P.)

ABSTRACT : Today the empowerment of women has become one of the most important concerns of 21st century. We observe in our day to day life how women become victimized by various social evils. Women Empowerment is the vital instrument to expand women's ability to have resources and to make strategic life choices.

Women play a vital role in society. They have contributed in all areas and there are so many examples in all fields.Thereis a need of time to frame the women empowerment programme at all levels. The great contribution expect from advocacy groups, policymakers, social researchers, health workers, social thinkers and sociologist for the women empowerment. Women Empowerment commission is a tool to eradicate various problem and provide right track for them.In this article, the main focus has been given on status, role, situation, authority and problems with the role of women empowerment of India.

Key Words : Women Empowerment, Education, Health, Socio-Economic Status. Crimes against women, Policy implications.

Introduction : The topic on Women Empowerment is a burning issue all over the world. Women empowerment and women equality with men is a universal issue.Women Empowerment refers to strengthening the social, economic and educational powers of women. It refers to an environment where there is no gender bias and have equal rights in community, society and workplaces. Women population is around 50% of the total population of the world. They have every right to be treated equally with men in every spheres of life and society. Traditionally, an Indian woman had four fold status-role sequences. These

were her role as a daughter, wife, housewife (homemaker), and mother.

Women empowerment is used both in general and specific sense. In general sense it means making women self-dependent and giving them all the freedoms and opportunities. In a specific sense, women empowerment means improving the position of women in the society's power structure.

In simple words, empowerment is giving power. Power is the keyword of the term empowerment. According to the International Encyclopedia (1999), power means having the capacity and the means to direct one's life toward desired social, political and economic goals or status. Power means control over material assets, intellectual resource and ideology. In Webster's English Dictionary, the verb empower means to give the means, ability and authority. Empowerment is a multi-dimensional social process that helps people to gain control over their own lives and in their society, by acting on issues that they consider as important. Empowerment occurs within sociological, psychological and economic spheres and at various levels such as individual, group and community and challenges our assumptions about the status-quo, asymmetrical power relationships and social dynamics.

The World Bank defines empowerment as "the process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices and transform those choices into desired actions and outcomes. Central to this process is action which both build individual and collective assets

and improve the efficiency and fairness of the organization and institutional context which govern the use of these assets." Economist BinaAgarwal defines empowerment as a process that enhances the ability of disadvantaged and powerless individuals or groups to challenge and change in their favour, existing power relationship that places them in subordinate economic, social and political position. Empowerment can manifest itself in acts of individual resistance as well as in group mobilization. Empowerment is multidimensional and refers to the expansion of freedom of choice and action in all spheres economic, political, social/cultural, personal and familiar to change the ones life". Thus empowerment is multi-dimensional gaining self-confidence and meaningful participation in decision making. As the foremost precursor to development and empowerment of women comprehensively seeks to ensure an equitable division of resources and carve a clear role for them in decision making. It helps them articulate their as well as other rights and participate actively in democratic processes. According to Swami Vivekanand, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of the women is improved.

Women empowerment processes certain characteristics, they are the following :-

1. Women empowerment is giving power to women; it is making women better off.
2. Women empowerment enables a greater degree of self-confidence and sense of independence among women.
3. Women empowerment is a process of acquiring power for women in order to understand her rights and to perform her responsibilities towards oneself and others in a most effective way.
4. Women empowerment gives the capacity or power to resist discrimination imposed by the male dominated society. 5.Women empowerment enables women to organize themselves to increase their self-reliance.
6. Women empowerment means women's control over material assets, intellectual resources and ideology.
7. Women empowerment challenges traditional power equations and relations. 8. Women empowerment abolishes all gender based discrimination in all institutions and structure of society.
9. Women empowerment means participation of women in policy and decision making process at domestic and public levels.
10. Women empowerment means exposing the oppressive power of existing gender and social relations.
11. Empowerment of women makes them more powerful to face the challenges of life, to overcome the disabilities, handicaps and inequalities.

The position and status of women in society has been changing from time to time. In Vedic India, woman was considered to be a goddess. No religious or social function was considered to be auspicious where woman was not present. She was called the “Ardhangini’ (the better half) of man. She had a fairly high status in society. All this shows the high esteem in which women were held in ancient India.

With the advent of Muslims in India, the position of women received a set- back. They had to go behind the veil. The British rulers, too, did not take any concrete steps to improve the status of women. It was only with the dawn of freedom that the position and status of women took a turn for the better. Our national leaders started working for the emanicipation of women. They were given their rightful place in all spheres of life. Discrimination on the basis of sex became a matter of the past.

A woman in olden days had to depend upon her parents, her husband or her sons for the whole of her life. But the modern even is as free as a bird. She no longer depends on others. Education has

raised her status. She is keen on becoming self-supporting. She likes to enter some profession. It does not mean that she wants to remain alone or unmarried. She longs to have respectable status. She does not like to be a dumb driven cattle.

As a result of all this, the woman broke out of the four walls of her house and started marching ahead in life. She joined the worldwide phenomenon of women. Today, the eve is certainly on the march. In fact, she has left man far behind in many fields. We have women legislators, women ministers, ambassadors, doctors, lawyers, teachers and officers. With the encouragement of co-education, modern girls have thrown off old complexes and they are marching shoulder to shoulder with boys in every field of life.

A modern girl is conscious of her position and importance in the society. She is no longer a dumb cow of the society. She competes with boys and ever sphere of life. She is full of self-confidence. She is an ambitious as the boys and wants to become a problem for the poor parents. A girl born to poor parents does not cut down her needs. She, too wants to enjoy life like her rich friends.

Women's Role in Society and politics : Women are the backbone of society. Society never complete without women.Men and women are the two wheels of life.There should be uniformity in both parties. But when we seethe structure of Indian society, it always gives the secondary status to the women. As per the development of education, the changes have been taking place in the position of women.After independence in India, there are the special women related articles created by experts. In the Indian constitution,the principle of gender equality is enshrined with preamble,fundamental rights, fundamental duties and directive principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favour of women. Empowerment is the one of the key factors in determining the success of development is the status and position of women in the society. For the healthy development of society there is a need to special focus on social, economical and political overall development of women.We need to augment our efforts for empowering women and enhance their progress. It is our moral, social and constitutional responsibility to ensure their progress by providing them with equal rights and opportunities. Today women with their smartness, grace and elegance have conquered the whole world.

Increased awareness and education has inspired women to come out of the four walls of the home. Many woman actively supported and participated in the nationalist movement and secured eminent positions and offices in administration and public life in free India. Traditionally Indian women exist because of the family and for the family.Just like their man counterpart, women are also fond of attending social functions and value her social life quite a lot. Previously, men-folk used to discourage women from leaving their households for attending social functions. Now the spread of education, especially that of women, and with that the changing social attitudes of educated women have changed the order.

Most women, even the educated, regard marriage as a matter of parental choice. Many young girls of the middle and upper classes are educated with a view to marriage rather than to careers. Again, many girls enter into careers apparently not because they want them, but because there is nothing else to be done until their parents find them husbands.The modern woman has started caring for her health, figure, cultural needs and interests, academic pursuits, social intercourse, religious activities recreational needs, etc

Women are generally not aware of the provisions related to the improvement of their own position. Even if they know about some of the provisions related to their rights of succession, marriage, or family, they do not desire to invoke them. Traditional dominance of the authority of the male parents, husband, and other elder members of the family often restricts the enjoyment of their legal

rights by the women. The materialization of these problems still depends largely upon the attitudinal changes in society.

During the independence movement, women were visible and active as nationalists, and as symbols of 'Mother India'. Gandhi, in particular, was instrumental in creating space for women through his non-violence (and some would argue feminized) mode of protest.Gandhi's legendary salt March initially excluded women, but due to demands from women nationalists he later realized the power of women organizers at the local level. His inclusion of women, however, was not located within a gender equality framework, but was a means to achieving a stronger and unified Indian state. The inclusion of women in the nationalist movement was also to debunk the British colonial assertion of "needing to save the poor, vulnerable women" of pre-independence India. As in many nationalist movements, women in India took part in the struggle, in turn propelling a women's rights movement. And, as seen historically in many post-colonial countries, the nationalist women's movement in India was confronted by the rebuilding of a patriarchal nationalist state. Women revolutionaries gave way to their male counterparts who (as a result of Partition politics) created a strong, male, and Hindu New India. The first post-independence LokSabha (the People's Council or the Parliament) had 4.4% women. The period between the early 1940's and late 1970's saw an emergence of the Indian women's movement, but it was not until the 1980s that the women's movement gained real momentum.

Educated women are just on the threshold of transition from tradition to modernity. The women themselves desire that their status and position in society should rise higher. Though a proper climate for such a change is still wanting, yet there have been many structural and statutory innovations for the improvement of their position. The traditional status and role sets of women are breaking up and new role-sets based on achievement, independence and equality are gradually coming up.Education of women has not only helped them to become aware of the political problems, but they are gradually becoming active participants in the political life. Some are enrolling themselves as members of political parties, attending party meetings, conventions, and carrying out political programs. Some women are attaining influential political stature of their own and have become instrumental in shaping the public opinion for the betterment of women's conditions in society.

Participation of Women in Socio-economic activities : The woman in modern times is entering into certain new fields that were unknown to the woman's sphere of role-sets. These are the woman's participation in economic, political, and social life.

The modern woman keenly desires to enter into a work career because of the pressing economic needs of the family. In middle class families, much emphasis is given to the maintenance of high standard of living. To fulfill the economic needs of the family and to achieve higher standard of living the woman participates in economic activities.

The empowerment of women would result in overall development of society both at micro and macro level. Active participation of women in economic activities and decisions, would contribute towards overall economic development.

The woman in modern times is entering into certain new fields that were unknown to the woman's sphere of role-sets. They are activating participating in social, economic, and political activities.

Gandhiji's vision that women must play an equal and important role in national development. However, the movement for raising the socio-economic status of women had involved generally the middle-class educated women in major urban centers while the great mass of rural women are yet to enjoy the rights and privileges as enshrined in the Constitution Women's equality in terms of education, employment, and power is still an

individual rather than a universal achievement. The majority of our women are still content to accept an inferior status. This is by and large due to the fact that, although legally women have equal rights with men, there are not enough jobs for women and working women are not adequately protected from exploitation.

Challenges and issues to women empowerment :
There are several constraints that check the process of women empowerment in India. Social norms and family structure in developing countries like India, manifests and perpetuate the subordinate status of women. One of the norms is the continuing preference for a son over the birth of a girl child which in present in almost all societies and communities. The society is more biased in favor of male child in respect of education, nutrition and other opportunities. The root cause of this type of attitude lies in the belief that male child inherits the clan in India with an exception of Meghalaya. Women often internalize the traditional concept of their role as natural thus inflicting an injustice upon them. Poverty is the reality of life for the vast majority women in India. It is the another factor that poses challenge in realizing women's empowerment. There are several challenges that are plaguing the issues of women's right in India. Targeting these issues will directly benefit the empowerment of women in India

1 Education : Extremely low rate of women literacy is the major curse and roadblock to women empowerment in India.

While the country has grown from leaps and bounds since independence where education is concerned,the gap between women and men is severe. While 82.14% of adult men are educated, only 65.46% of adult women are known to be literate in India. The gender bias is in higher education, specialized professional trainings which hit women very hard in employment and attaining top leadership in any field.

2 Poverty : Poverty is considered the greatest threat to peace in the world, and eradication of poverty should be a national goal as important as the eradication of illiteracy. Due to this, women are exploited as domestic helps. Poverty in India is plaguing many issues and posing the greatest threat. Condition of poor women is far pitiable than their middle class or rich counterparts as far as women empowerment is concerned. Widespread poverty leads to the exploitation of women. Sex slaves, selling girls and women, forced marriage and more crimes of these kinds are directly linked to poverty. State of Andhra Pradesh, which is a home to many rural poor, accounts for the half of the sex trafficking cases in India. Because of the inherent superiority complex among the males, they often doesn't allow their female counter-part to rise as high as them.

3 Health and Safety : The health and safety concerns of women are paramount for the wellbeing of a country and is an important factor in gauging the empowerment of women in a country. However there are alarming concerns where maternal healthcare is concerned.

4 Professional Inequality : This inequality is practiced in employment sand promotions. Women face countless handicaps in male customized and dominated environs in Government Offices and Private enterprises.

5 Morality and Inequality : Due to gender bias in health and nutrition there is unusually high morality rate in women reducing their population further especially in Asia, Africa and china. Household Inequality: Another hurdle is the denial of women's participation in the family decisions. Family is making women dependable and forcing a second grade status on her. Household relations show gender bias in infinitesimally small but significant manners all across the globe, more so, in India. High level of domestic responsibilities, restrictions to participate in social, economic and religious activities.In our society, the boy-child often gets preference for education and healthy diet over the girl child.Preference for male-child still exist among many families in the society.

Trend of worshipping is still there but except for this scenario in modern India seems to be entirely different where woman is regarded as a second grade citizen. Gender discrimination, gang rapes with girl and women of every age, acid attacks and other kinds of violence against women are happening in every city of India. It is hard to figure out why and what has changed the status of women in India and when it became such a flashy issue.

In reality crime against women is on rise in India. Reports by the National Crime Records Bureau are the real eye openers which throw light on the total number of different crimes against women. In year 2006 number of reported cases of rape were 19,348 whereas the number rose to 24,923 in 2012. Reported cases of dowry deaths in 2006 were 7,618 and in 2012 these were 8,233. Similarly, rise in other crimes against women such as torture, molestation, sexual harassment, immoral trafficking, importation of girls, kidnapping and abduction has also been reported.

As per the latest data from National Crime Records Bureau, the crime rate against women rose from 41.7% to 53.9%, between 2011 and 2015. Up to 3,27,394 cases were reported in 2015 alone, including 34,651 cases of rape, 4,437 cases of attempted rape, 59,277 kidnapping and abductions, 7,634 dowry deaths, and a whopping 1,13,403 cases of domestic cruelty, among others. Unfortunately, 'reported' is the key word here, given that a majority of crimes against women remains unregistered, even in 2017. Therefore, as upsetting as these numbers may seem, they barely paint the whole picture.

Solution : Though government is taking all the necessary steps to empower women but something is still lacking and creating a gap between the constitutional position and the realty. The solutions for empowerment of women includes the following:

Education through mass communication is very important. Both women and men should be made aware of their responsibilities to promote and practice gender-equality.Gather national data and identify the areas where instances of violence and gender-inequality is the most. This data can be used by the Government, NGOs and field workers to raise the status of women.The society should be made aware that both boy-child and girl-child are equal, and they both should have equal access to resources.

Women are the building blocks of our society. She must be made strong for a stronger society and her status should come at par with men. To promote gender equality and to empower women in India, the United Nations Development Programme created Millennium Development Goals (MDG). Out of eight goals, the third MDG is constituted for India. Target was to achieve gender equality in primary and secondary education by 2005 but India failed to achieve the said target. Next target is to eliminate gender disparity in all levels of education by 2015. This is still a big challenge.

Certain changes have also been made in the Constitution of India. Woman has been given the right to divorce under certain circumstances in the modified Hindu Marriage Act. Daughter of the family has been provided with the right in the property of her parents under the Hindu Succession Act.

In 1985 government took a step for the overall development of women and children by creating the department of the Ministry for Women and Child Development under the Ministry of Human Resource Development. In 2006 this department was upgraded to the status of a Ministry. The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 was enacted by the Ministry. It also brought in a unique law – the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. It launched several schemes for the welfare of women and children such as the Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG), Indira Gandhi MatritvaSahyogYojana (IGMSY) and the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme etc.

An other important factor that determines the empowerment of women in India is the health and wellbeing of females. But maternal health in India is still in a shocking state. Though the maternal mortality rate (MMR) is dropping but India has to cover a long way. According to the data released by the Registrar General of India, there is a 16% drop in MMR in 2011-12 as compared to 2007-09. On the other hand UNICEF's website has updated that there is a decrease in the child mortality rate but neonatal and maternal mortality is almost the same in the South Asian countries. In the new born deaths, contribution of India is a quarter of the world total. Mother's health plays a vital role in MMR. It can be improved by providing nutritious diet during pregnancy. This is possible only if India works hard to eradicate poverty. NGOs and government are working towards it but still lot more is required to be done.

Women's organization have come to be recognized as the main source of power, position and strength for women in modern India. A women fight injustices perpetrayed by men single handed or also. But, she can do the same collectively through organizations. Women SHGs in rural area, under Stree Shakti Scheme, are doing yeomen service in organizing women power. Women from different sections are being brought together and organized into an association to wage a war on liquor shops and gambling dens, matakacentres etc. and fight for abolishing age old practices like wife beating, polygamy, dowry-connected harassment, devadasi system, child marriages, etc. Besides, the SHG are providing employment opportunities to large masses of illiterate, ignorant and suppressed women folk. A proper leadership among women will go to a long way in empowering them.

The single most resource that liberates people from poverty and empower them is knowledge. A society by using knowledge through all its constitutions, endeavours to empower and enrich its people and thus will become a knowledge society. Such knowledge society will need empowerment at all levels and among all the key actions of the society. At this juncture, it is essential to see the possibilities of women's empowerment through information technology. Access to information is the key for economic, social and political empowerment of women. So far no other technology claimed to have given the instant, uncensored, practically feasible, economically viable information to the women folk than the information technology. IT poses new forms of learning, education, health services, livelihood options, goverence mechanism and e-commerce options which would lead to the ultimate goal that is woman's empowerment.

Freedom is good but too much of freedom is bad. The modern girl should not employment westernize herself. She should copy only the best of the West without losing the best of the East. She should not forget the glorious traditions of the Indian women.

An Indian woman is still deprived of her rights. In addition to this there is a demographic difference. Most of the aroma of liberation is enjoyed by the urban woman but not by her rural counterpart. Rural women and even some of the urban are living a miserable life, entangled in poverty, superstitions and slavery. Still there is a huge gap between the Laws made and their enforcement.

For the empowerment, she must be made economically independent. Without such independence all the laws, schemes and policies for her welfare would merely be written documents.

Mindset of the people especially male towards women is also a challenge. It needs a huge change. At the same time value and behavior system of the society should certainly undergo transformation to incorporate new thinking.

The Government programmes for women development began as early as 1954 in India but the actual participation began only in 1974. At present, the Government of India has over 34 schemes for women operated by different

department and ministries. Some of these are as follows;

1. MahilaKoshyojana. This is first plan started for especially rural women of India in which self employment, stress on msme and supplementary occupation are the most priority factors.

2.Training and employment programme for women(TEPW.) To build up the confidence, economically strong and for enhancing the productivity are the main targets of this plan.

3. RashtriyaMahilaKosh (RMK).For social and economical changes, financial improvements through various programmes are the main objects of this plan.Micro finance to poor women, agriculture women, shopkeeping and handcrafts etc are important objects of this plan.

4.Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG).This is especially well-known for the overall development of teen age girls for the issues like nutrition, education, medical facilities and eradication of the different problems

5. Central Social Welfare Board (CSWB).This scheme is especially famous for stimulation of the NGOs which work for development of women.

6. Indira Gandhi MatritvaSahyogYojana (IGMSY.) For the improvement to the health and nutrition status of pregnant, lactating women and infants, child vaccination with sort out the various problems.

7. Swayam Siddha yojana. Creation of self help groups with financial support and availability the fund for poor women in society.

8. Short Stay Home for Women and Girls (SSH). Arrangement of temporary accommodation of deprived,mentally affected, very poor, widow, exploited and rejected by society and family. With the help of this plan various works knowledge given and try to become self to such type of women.

9. Swadhar : This plan is especially for the support of women those reallywant to do the advance type of work. Some financialsupportgiven by government to start the occupations.

As a result of a vibrant women's movement in the last 50 years, policies to advance human rights for women in India are substantial and forward-thinking, such as the Domestic Violence Act (2005), and the 73rd and 74th Amendments to the Constitution that provide reservations for women to enter politics at the Panchayat level. There are multiple national and state level governmental and non-governmental mechanisms such as the Women's Commission to advance these policies, and the implementation of these policies is decentralized to state and district-level authorities and organizations that include local non-governmental organizations.

Conclusion : Community awareness on the benefits of empowering women should be carried out in order that the empowerment may be supported by the community as whole. For the suitable construction of society, there is need to give special attention on women empowerment in India. Also traditional attitude has to change regarding women. Awareness programme,education and positive role of every indivisible will help to development the status of women in India. Strictly implementation, creation and support of legislative, judiciary will be beneficial to sort out the women related problems in India. To stop the women exploitation, rape sexually harassment, acid throwing, domestic violence, child marriages and female foeticide with effective instruments and control on the these problems. Above all women must empower themselves to actually change their status in the society then only women empowerment will happen in realty but not in illusion.

When women move forward the family moves, the village moves and the nation moves". It is essential as their thought and their value systems lead the development of a good family, good society and ultimately a good nation. The best way of empowerment is perhaps through inducting women in the mainstream of development. Women empowerment will be real and effective only

when they are endowed income and property so that they may stand on their feet and build up their identity in the society. The Empowerment of Women has become one of the most important concerns of 21st century not only at national level but also at the international level. Government initiatives alone would not be sufficient to achieve this goal. Society must take initiative to create a climate in which there is no gender discrimination and women have full opportunities of self decision making and participating in social, political and economic life of the country with a sense of equality.

References :

- Duflo E. Women's Empowerment and Economic Development, National Bureau of Economic Research, 2011
- * Baruah B. Role of Electronic Media in Empowering Rural, 2013
- Goswami, L. Education for Women Empowerment. ABHIBYAKTI: Annual Journal, 1, 17-18, 2013
- Kadam, R. N. Empowerment of Women in India- An Attempt to Fill the Gender Gap. International Journal of Scientific and Research Publications, 2(6), 11-13, 2012
- Nagaraja, B. Empowerment of Women in India: A Critical Analysis. Journal of Humanities and Social Science (IOSRJHSS), 9(2), 45-52, 2013
- Deshpande, S., and Sethi, S., Role and Position of Women Empowerment in Indian Society. International Referred Research Journal, 1(17), 10-12, 2010
- Dr. DasaratiBhuyan " Empowerment of Indian Women: A challenge of 21st Century" Orissa Review, 2006
- Medha Dumas hi, "Women Empowerment of Indian : A Socio Economic study of Delhi" Mittal Publications, Delhi, 1987
- * DhrubaHazarika "Women Empowerment in India : a Brief Discussion" International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 1, Number 3 (2011)
- LeelaMenon, "Women and Social attitude", Kerala, March 2004,
- United Nation Development Programmes (UNDP), Human Development Report 2006.
- Sharma Sheetal, "Empowerment of women and property, rights key to rural development", Kurukshetra, 54, No. 8, June 2006,
- ArundhatiChattopadhy, "Women and entrepreneurship", Yojana, Vol. 49, No. 1, January 2005,
- Gupta V.S., "Capacity building for effective empowerment of women", Kurukshetra, 50, No. 8, June 2008,
- Kamla Basin, "Education for Women Empowerment- Some reflection", Adult Education Development, March 1992.
- Bhagyalakshmi J., "Women empowerment : Miles to go", Yojana, Vol. 48, No. 8, August 2004,

IN AN ANTIQUE LAND
A COUNTER-NARRATIVE OF COLONIALITY

Dr. MUKESH PAREEK (Ph.D)
University of Rajasthan, Jaipur

A conference on "Commonwealth Studies" is a poignant reminder of the conquerors, the rulers, the imperialists who determined the history of the world and changed the events of our lives with a disjunctive violence. It is also a reminder of the fact that imperialism was more than economic exploitation and political domination. Coloniality and imperialism are relationships that have had a cultural, intellectual and social impact which is even more insidious than the naked fact of political domination. As the term 'post-colonial' suggests, the fall-out of colonialism is still very much with us.

In Salman Rushdie's famous phrase, this present historical moment is when "the Empire writes back"; the periphery is speaking and the centre is listening. However, the intellectual power centre is still to shift. In Aijaz Ahmad's words, there is still only a limited range of "authorised questions" set by the intellectual centre that may be answered in the works of post-colonial literature and one of the central issues that may be addressed is that of the concept of "nationhood." As Ahmad comments, even to a sensitive and liberal critic like Frederic Jameson

The essential task of a 'Third World' novel, it is said is to give appropriate form (preferably allegory, but epic also, or fairy tale, or whatever) to the national experience. The range of questions that may be asked of the texts....must predominantly refer, then, in one way or another, to representations of colonialism, nationhood, post-coloniality, the typology of rulers, their powers, corruptions and so forth." (Ahmad 124)

We can see the implications of this position when we look at the valourised or canonised Third World novels-Chinua Achebe's trilogy, Ngugi's novels, Garcia Marquez' Children and Shame. Much of Indian writing in English has been concerned with the construction of nationhood like Sashi Tharoor's The Great Indian Novel or even in a different way, Vikram Seth's A Suitable Boy. Most of these writers attempt to create an epic vision of the past by multiple narratives, the use of myths, fantasy, allegory. All are concerned with political equations in some way, yet they are focussed on the ruling classes or coteries. The people, if they do appear at all, are usually disassociated from the political process, or are shown as defeated, disillusioned with the corrupt, power-hungry new rulers. Most of these novels are indictments of the post-colonical condition; often they also seem to be implicitly suggesting that the new corrupt rulers are no better than the foreign rulers-they may even be worse. Naturally these are sentiments that the metropolitan West finds reassuring.

It is in this context that Amitav Ghosh's In An Antique Land deserves our attention. This novel focusses on the interrelationships of the people rather than of nation-states and their rulers. There are three important spatial tropes-India, Egypt and the 'West'. While India and Egypt have ancient ties which are myriad, the West is represented as the powerful interventionist in the relationship between the two. More importantly, the West, its rhetoric, its ideologies, its ways of thinking have been superimposed on the histories of the two 'antique lands.' Ghosh tries to show that the intervention of the West has destroyed the processes of dialogue, exchange, assimilation and syncreticism of the peoples of the two nations. Instead, there is the metaphysic of domination, classification and violence which Ghosh characterises as 'Western.' He describes how in 1500 A D a Portuguese fleet came with a letter from the King of Portugal to the Hindu ruler

of the city-state of Calicut demanding that he expel all Muslims. As the Hindu ruler remained obstinate in his refusal to comply, the Portuguese fleet attacked and conquered what is today part of Gujarat. A hastily put together army of the Muslim potentate of Gujarat, the Hindu ruler of Calicut, and the Sultan of Egypt could offer little resistance. "As always, the determination of a small, united band of soldiers triumphed easily over the rich confusions that accompany a culture of accommodation and compromise." (Ghosh 288) A modern parallel is established as Ghosh closes the novel. Almost five centuries later, the Gulf War again disrupts history and this time characters like Nabeel "vanish into the anonymity of History." (353)

The construction of the text is itself complex. There are basically two strands of narrative. In the first, Ghosh looks at the life of a twelfth century Indian slave Bomma who works for an Arab Jewish trader Abraham Ben Yiju and tries to reconstruct his history, while the second portrays simultaneously his own experiences as an Indian researcher in an Egyptian village. Let us look at the strand of the narrative which deals with the ancient times first. Ghosh's choice of the Indian slave as the focal center of the narrative is itself significant. He is literally a person who inhabits the footnotes of history. To quote the opening lines :

The salve of MS H. 6 first stepped upon the stage of modern history in 1942. His was a brief debut, in the obscurest of theaters, and he was scarcely out of the wings before he was gone again-more a prompter's whisper than a recognisable face in the cast,

(Ghosh 13)

From this anonymity, Ghosh attempts to rescue the life of this slave who was so much part of Ben Yiju's household that his friends would enquire after Bomma in their letters. In tracing this fascinating history, Ghosh makes us aware of how ancient the links are between what is today Egypt and what is today India. The cross-dissemination of cultures, religions, and traditions is brought to light through the existing correspondence of Ben Yiju with his family and friends, as well as by Ghosh's digressions' which describe the historical events of the past. All these coalesce marvelously to highlight the syncretism of culture. To take just two examples : first the passage which traces the history of the home of Abraham Ben Yiju, master of Bomma-a Roman fortress called Babylon. The fort was built in 130 A D by the emperor Trajan on the "site of an even earlier structure." Of the two massive towers of the entrance to the fort, on has been incorporated several centuries ago into the structure of a Greek Orthodox Church. In Ben Yiju's time, it was a port which was busier than Baghdad and Basra combined. Through this gateway entered the Arab general in 641 which was the decisive event that market the Muslim victory over the Christian powers in Masr or Egypt. He laid the foundations of a new city which soon replaced Alexandria as the country's capital. Three hundred years later, a general in the army of the Fatimid dynasty who was formerly a Greek slave, conquered the Egyptians and marked the boundaries of a new township, al-Qahira. "It was this name that was to pass into European languages as Cairo, Le Caire and the like." (36) The passage recreates for us a time when these antique lands of the Middle East and the East were the centres of trade and commerce, of production and of culture. To quote :

With the pivotal ascendancy of the Fatimid Empire, it [Al-Qahira] had come to play a pivotal role in the global economy as the entrepot that linked the Mediterranean and the Indian Ocean : the merchandise that flowed through its bazaars came from as far afield as East Africa, Southern Europe, the Western Sahara, India, China and Indonesia... the juncture of some of the most important trade routes in the known world and the nucleus of one of the richest and most cosmopolitan centres of the world. (37-8)

Today this ruin is "a giganitic open refuse-pit, an immense rubbish dump" (38) but "incredible as it may seem, excavations in this suppurating wasteland have yielded huge quantities of Chinese pottery and other riches : it

was here that some of the earliest and most valuable fragments of Indian textiles have been found" (39). This passage makes us aware of among other things, the history, geography and economics of a world before colonialisation, of the perpetual shifts in religious powers, of globalisation of trade before GATT. This ancient center is now a "suppurating wasteland." Cairo (and Egypt) like all the countries or regions mentioned in this passage-East Africa, Southern Europe, the Western Sahara, India and China-are among the poorest, least productive countries in the post-colonial world. This passage also shows us the multiplicity of cultures that created the city. The Greeks, Muslims, Jews, the Orientals and the Christians all contributed in the building of Cairo and Cairo is, the author tells us, "Egypt's metaphor for itself." (32)

The other passage I would like to look at is the one where Ghosh is trying to unravel the true name of the slave. He discovers that it was probably 'Bomma' (in the ancient Judeao-Arabic script it was represented by the three characters BMH). His search takes him into the history of the South Indian tribe, the Tulus and the process of Sanskritisation of their myths-where some of the "deities would occasionally appear within the mists of high Sanskritism, while other fell from favour and vanished into the nether world" (252). Thus Ghosh is astonished to discover that the Tulu Brahma is not the four-headed, four-armed image accompanied by a goose of the classical iconography, but a warrior deity with curling moustaches, holding a sword in one hand. He learns that this was the principal figure in the Tulunad-Bhuta pantheon originally called Berme of Bermere. "Over time, with the growth of Brahminical influence the Tulu deity Berme had slowly become assimilated to the Sanskritic deity 'Brahma'." (254) Again, the syncreticism of religions and culture is revealed in the search for the salve's true name. The processes of assimilation and the difficulties of knowing or even recognising these seams of history and culture become evident.

The narrative which is interwoven with that of Ghosh's anthropological and archeological researches is that of his experiences of the present. He goes to the villages of Lataifa and Nashawy to learn the language and culture of the Egyptians. Whereas the narrative mentioned earlier stresses the inter-relationships between countries and peoples, this strand of the narrative seems to concentrate on the tendency towards exclusion. Some of the most humorous passages in the text are those when the fellahs (peasants) of Egypt react to Ghosh's account of India and Hinduism. These are a few of the exchanges : Ustaz Mustafa who has "real all about India when I was in college in Alexandria" says :

'There is a lot of chili in the food and when a man dies his wife is dragged away and burnt alive'

'Not always', I protested....

'And of course you have Indira Gandhi and her son Sanjay Gandhi, who used to sterilise the Muslims....'

'No, no, he sterilised everyone', I said.

His eyes widened and I added hastily : 'No, not me, of course but....'

'Yes', he said, nodding sagely. 'I know'. (46)

Later Ghosh admits that he is a Hindu, reluctantly because for him it is "a religious identity largely by default" (47) to which Ustaz Mustafa says :

'What is this 'Hinduki' thing ?...If it is not Christianity nor Judaeism nor Islam what can it be ? Who are its prophets ?

'It's not like that', I said. 'There aren't any prophets....'

'So you are life the Magi?' he said, bright-eyed. 'You worship fire then?'

I shook my head vaguely, but before I could answer....he said smiling coquettishly, 'I know .....it's cows you worship--isn't that so?'

There was a sharp, collective intake of breath as Jabir and the other boys recoiled, calling upon God in whispers, to protect them from the Devil. (47)

Scenes like these become distressingly familiar to the narrator in the text, but these exchanges serve to highlight two important aspects of modernist ideology-first, the ease with which the 'Other' is constructed and rejected as 'impure' or abnormal. Secondly, we the Indian readers, also receive a jolt along with the writer when we come face to face with the observers' vision of India and Hinduism.

Ghosh also shows us how one of the strands of ideology shared and revered by the two 'Antique Lands' is the concept of modernity. There are two scenes which show this poignantly. In the first, Ghosh is summoned by his neighbour to tell him if the 'Makana Hindi' (the Indian machine) he has bought is good. It turns out to be a water-pump. Ghosh is aghast "I knew nothing at all about water-pumps; indeed I could not recall ever having noticed one before coming to latifa". (72) But he has to pronounce the machine 'excellent' to the great relief of his friend. As a result, Ghosh regains some of his stature in the village. This incident deeply disturbs him.

I stayed up a long time that night, marvelling at the respect the water-pump had earned me; I tried to imagine where I would have stood in Jabir's eyes if mine had been a country that exported machines that were even bigger, better and more impressive-cars and tractor perhaps-not to speak of ships and planes and tanks. I began to wonder how Lataifa would have looked if I had had the privilege of floating through it protected by the delegated technology, of looking out untroubled through a sheet power of clear glass (74)

Even more poignant is the scene which finds Ghosh and the Imam "delegates from two superseded civilisations, vying with each other to establish a prior claim to the technology of modern violence" (236)....

It seemed to me that the Imam and I had participated in our own final defeat, in the dissolution of the centuries of dialogue that had linked us : we had demonstrated the irreversible triumph of the language that had usurped all the others in which people once discussed their differences. We had acknowledged that is was no longer possible to speak, as Ben Yiju or his slave, or any one of the thousands of travellers who had crossed the Indian Ocean in the Middle Ages might have done.....Instead....we had both resorted.....to the very terms that would leaders and statesmen use at great, global conferences, the universal, irresistible metaphysic of modern meanings. (237)

Ghosh is prodded out of his despair by the good-natured laughter of 'Eid and Khamees who tell him "Do not be upset, ya doktor. Forget about all those guns and things." and promises to visit him in India, even to leave with him. Thus, the possibility of dialogue in the language of friendship and community is re-established.

The West is also shown as the imperial power in the world of knowledge. Bomma's story ends in Philadelphia where the manuscripts are kept. The manuscripts are scattered far from their origins, in England, the United States and Russia. The history of these peoples has been appropriated, classified and housed in the 'West'. Facts are distorted "in the process of shaping them to suit the patterns of the Western academy." (342) Yet the novel ends with the discovery that "in defiance of the enforcers of History, a small remnant of Bomma's world had survived" (342) in the form of the tomb of Rabbi Abu-Hasira of Morocco.

This novel makes us rethink our notions of Time and Space as the title itself suggests. The choice of the word 'Land' rather than nation or even country undermines the modernist project of nationalism. While the word 'Antique' is destabilised by the implied present of the phrase In an Antique Land, the title posits the text as one of "the counter-narratives of the nation that continually evoke and erase the totalising boundaries both actual and conceptual-disturb those ideological manoeuvers through which 'imagined communities' are given essentialist identities". (Bhaba 300)

One way in which this is done in the text is to focus on the process of migrancy. While the

'migrant intellectual' has been valourised by writers like Bharati Mukherjee and Salman Rushdie, in this novel, Ghosh examines many other kinds of migrancy. Discussions of nationalism often ignore its 'Other' that is the creation of the exile, the migrant, the refugee. By accepting the nation as the 'given', we over look the fact that this is a relatively modern conceptual construct and that partitions and boundaries are, as Amitav Ghosh's earlier novel suggests "Shadow Lines."

The travels of Ben Yiju are motivated by economic concerns similar to those of the fellaheen who go to work in Iraq. Amitav Ghosh himself is on a search for knowledge while the German, British and American 'Orientalists' had already travelled these same roads. Edward Said points out one way of challenging the very basics of the very art and theory of government is to challenge the principle of confinement because "to be governed, people must be counted, taxed, educated, and of course ruled in regulated spaces." The nation-state cannot understand or accept those who do not fit into the neat categories it has created. Thus the police officer at the tomb of Sidi Abu-Hasira is confounded when he sees Ghosh's passport and finds he is not Israeli. Nor is he Jewish, Muslim or Christian-naturally he assumes that "There had to be something odd afoot." (335) The senior officer is at pains to maintain his distance from Ghosh's companion Mohsin, by denying "the protective bonds of neighbourhood and kinship....the accustomed terms of communication those immemorial courtesies of village life, by which people strove to discover mutual acquaintances and connections." (337) It is, according to Said, these migrant workers, refugees, immigrants, students and other such groups who "constitute a real alternative to the authority of the state." (Said 395) The creation of the frameworks, the boundaries of nations, has also automatically created the margins, the outsiders. Ghosh seems to be in agreement with Frantz Fanon's sentiment that "national consciousness, which is not nationalism is the only thing that will give us an international dimension." (qtd. in Bhaba 4).

Ghosh's tendency towards syncreticism and breaking barriers is reflected in the construct of the text itself. Breaking away from the traditions of both realism and magical realism, Ghosh's Text a combination of autobiography, history, anthropology, travelogue and fiction.

In this text, Ghosh seems to be responding to Said's call in Culture and Imperialism :

The major task is to match the new economic and sociopolitical dislocations and configurations of our time with the startling realities of human interdependence on a world scale. We need to go and to situate these in a geography of other identities, peoples, cultures, and then to study how, despite their differences, they have always overlapped one another, through unhiedrarchical influence crossing incorporation, recollection, deliberate forgetfulness, and of course, conflict. (Said 402-3)

Ghosh seems to me to be one of the few novelists who are today offering an alternative to the post-colonial trend of narrating the nation. In an Antique Land presents us with a truly subversive look at history, while suggesting possibilities of an alternative discourse of dialogue, rather than domination.

WORKS CITED

Ahmad A. In Theory, Verso, London : 1992

Bhabha Homi K. etd. Nation and Narration, Routledge, London : 1990

Ghosh A. In an Antique Land, Ravi Dayal Publishers, Delhi : 1992

Said E. Culture and Imperialism, Vintage, London : 1994.

INDIA : AN EVER EVOLVING NATION

Narita Ahuja
Assistant professor, Dept. of Commerce, NBGSM College, Sohna.

ABSTRACT : This paper annotes the status of Indian economy since Independence. The economy of India is a developing mixed economy. It is the world's sixth-largest economy by nominal GDP and the third-largest by purchasing power parity (PPP). It covers a broad stature of enormous aspects of our economy from population to poverty, from education to unemployment, from FDI to GDP'S, from Demographics to Statistics. It simply generates the information about the past history of the country, current scenario and a glimpse of tomorrow. The long-term growth prospective of the Indian economy is positive due to its young population, corresponding low dependency ratio, healthy savings and investment rates, and increasing integration into the global economy.

KEY-WORDS : GDP, FDI.

METHODOLOGY : For this study, descriptive methods are followed and secondary data has been collected. For this study data and information has been collected from various books, Research Article, Magazines, Research Journal, E-journal, Report of UGC, and Report of the higher education and Websites.

OBJECTIVES :

- To analyse the current status of Indian economy through the understanding of past and present figures of GDP, Education, Population, etc.
- To make a judgement about the future growth and development in the various sectors.

INTRODUCTION : With 1.27 billion people and the world's third-largest economy in terms of purchasing power, India's recent growth and development has been one of the most significant achievements of our times. Over the six and half decades since independence, the country has brought about a landmark agricultural revolution that has transformed the nation from chronic dependence on grain imports into a global agricultural powerhouse that is now a net exporter of food. Life expectancy has more than doubled, literacy rates have quadrupled, and health conditions have improved. India will soon have the largest and youngest workforce the world has ever seen. At the same time, the country is in the midst of a massive wave of urbanization as some 10 million people move to towns and cities each year in search of jobs and opportunity. It is the largest rural-urban migration of this century. Massive investments will be needed to create the jobs, housing, and infrastructure to meet soaring aspirations and make towns and cities more liveable and green.

HISTORY OF INDIA

[INDIA AFTER INDEPENDENCE]

After India got independence from colonial rule in 1947, the process of rebuilding the economy started. India went for centralized planning. The Five Year Plans which successfully transformed erstwhile USSR were made a tool for development. First five year plan for the development of Indian economy came into implementation in 1952. Being largely a agrarian economy, investments were made in creation of irrigation facilities, construction of dams and laying infrastructure. Due importance was given to establishment of modern industries, modern scientific and technological institutes, development of space and nuclear programmes. However, despite all efforts on economic front, the country did not develop at rapid pace largely due to lack of capital formation, cold war politics, defense expenditure, and rise in population and inadequate infrastructure. From 1951 to 1979, the economy grew at an average rate of about 3.1 percent a year in constant prices, or at an annual rate of 1.0 percent per capita. During this period, industry grew at an average rate of 4.5

percent a year, compared with an annual average of 3.0 percent for agriculture.

The rate of growth improved in the 1980s. From FY 1980 to FY 1989, the economy grew at an annual rate of 5.5 percent, or 3.3 percent on a per capita basis. Industry grew at an annual rate of 6.6 percent and agriculture at a rate of 3.6 percent. A high rate of investment was a major factor in improved economic growth. Investment went from about 19 percent of GDP in the early 1970s to nearly 25 percent in the early 1980s. As a result, during the late 1980s India relied increasingly on borrowing from foreign sources. This trend led to a balance of payments crisis in 1990; in order to receive new loans, the government had no choice but to agree to further measures of economic liberalization. This commitment to economic reform was reaffirmed by the government that came to power in June 1991.

Liberalisation and its effects (1991 onwards) : While commending his first budget in 1991 Dr Manmohan Singh had quoted Victor Hugo and said, "No power on earth can stop an idea whose time has come. The emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea". Since then economy has progressed immensely with GDP progressing at the rate of 6-8% per annum. The GDP (nominal) has grown from US$ 267.52 billion in 1992 to US$ 1.85 trillion in 2012. India is third largest economy of the world and a preferred FDI destination. India's foreign trade reached US$ 785 billion in 2012. India's major industries include information technology, telecommunications, textiles, chemicals, food processing, steel, transportation equipment, engineering goods, cement, mining, petroleum, machinery, software and pharmaceuticals. Major agricultural products include rice, wheat, oilseed, cotton, jute, tea, sugarcane, potatoes, cattle, sheep, goats, poultry and fish. In 2011–2012, India's top five trading partners are China, United Arab Emirates, United States, Saudi Arabia and Switzerland. The percentage share of various sectors in the economy in the year 2011-12 is given below. The high contribution of services and manufacturing sector indicates the huge progress made by Indian economy since its Independence when it was predominantly agrarian economy (59% in 1951).

PRESENT SCENARIO OF INDIAN ECONOMY

SRENGTHS OF INDIAN ECONOMY

After several decades of sluggish growth, the Indian economy is now amongst the fastest growing economy in the world. Economic growth is currently 8-9%, second only to China.

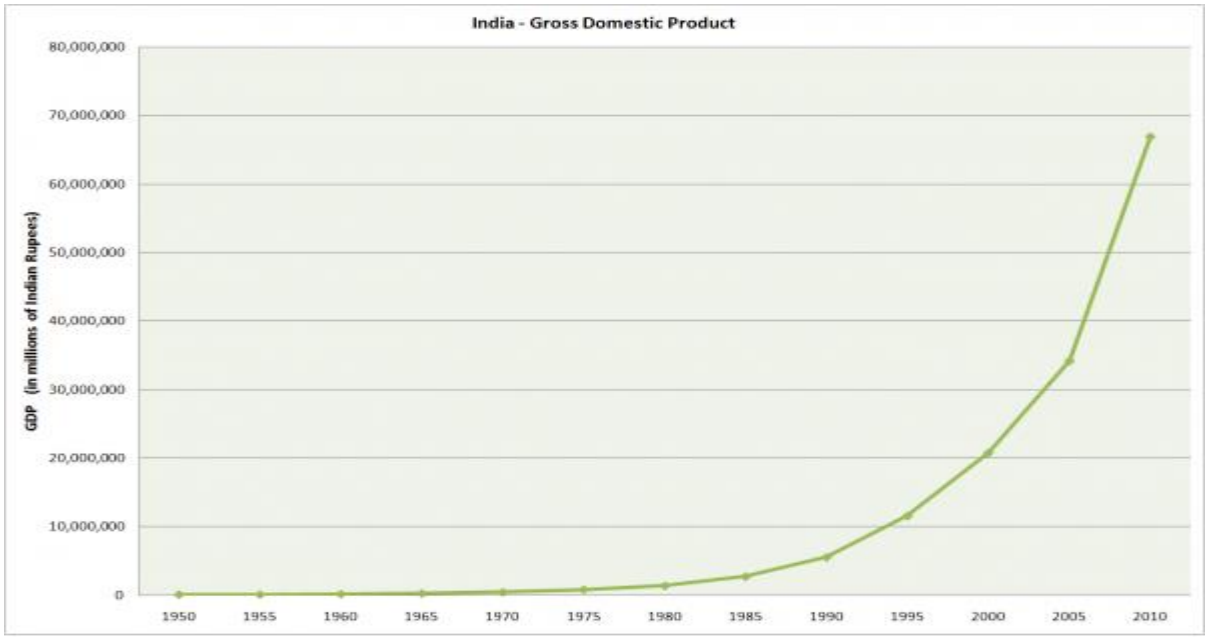

Despite several problems facing the Indian economy, many economists point to potential strengths of the Indian economy which could enable it to continue to benefit from high levels of economic growth in the future.

1. **Demographics of India are favourable.** India still has a positive birth rate meaning that the size of the workforce will continue to grow for the foreseeable future. (unlike China) A rising workforce helps to increase saving and investment. It also enables increased productivity.
2. **There is much scope for increases in efficiency**. The infrastructure of India is so bad in places that even moderate improvements could lead to significant improvements in the productive capacity of the economy.
3. **India is well placed to benefit from globalisation and outsourcing.** A legacy of the British Empire is that India has one of the largest English speaking populations in the world. For labour-intensive industries like call centres, India is an obvious target for outsourcing. This is an economic development likely to continue in the future.
4. **Education**. India has a relatively high level of literacy for average GDP per capita levels. The right to elementary education (from 2002 act) has helped literacy rise from 52.2% in 1991 to 74.04% in 2011
5. **Positive Growth forecasts** A recent study from Goldman Sachs, forecast that India could growth at a sustainable rate of 8% growth until 2020. However, it is worth noting that this assumed Indian would make several supply-side policies such as labour market deregulation and improvements in education and training.
6. **Comparative advantage in labour-intensive industries**. India will also benefit from the liberalisation of free trade in recent years.
7. **Largest Car producer**. India is one of the world's leading producers of small cars/mopeds. In 2013/14, India produced 21.48 million vehicles (mostly two and three-wheelers) making it one of the biggest car producers in the world – focusing on a successful niche of cheap motorbikes for the Asian market.
8. **Growth in new companies**. India has become a hub for IT start-ups, with the third highest level of business start-ups in 2014–15
9. **Attracting more FDI**. Despite rigid regulations in planning and start-ups, India has attracted $36.5 billion of FDI in 2011, a significant increase on previous years and a sign multinational companies are increasingly valuing India's growing economy and consumer class. This FDI is important for financing India's current account deficit.
10. **Remittances**. India has an important segment of its workforce working overseas (e.g. Middle-East). Foreign remittances to India amounted to US$68.91 billion in 2015 – 3.5% of India's GDP.
11. **Growth in trade Indian exports have grown from**

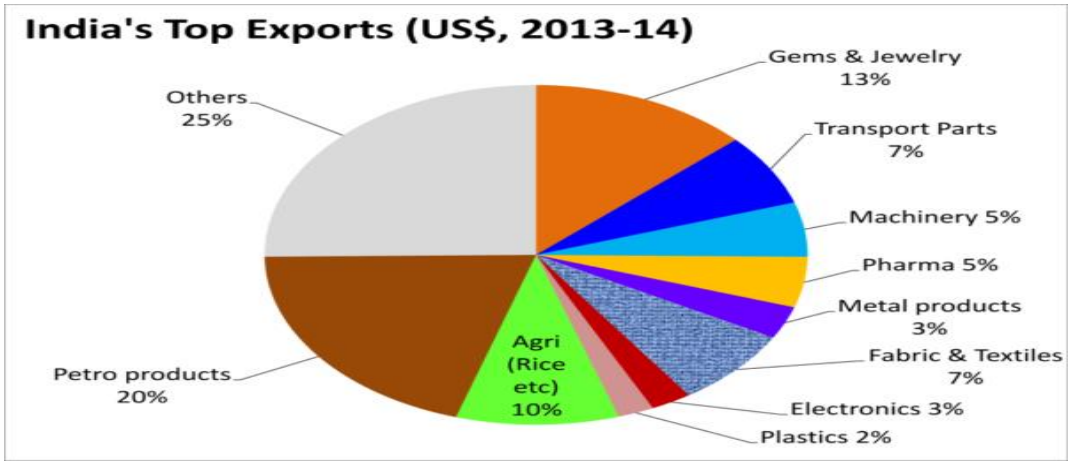

Foreign trade accounted for 48.8% of India's GDP in 2015.

12. **Tourism**. Tourism is a growth market for India, attracting foreign currency and creating employment. The tourism sector is forecast to grow by annual rate of 7.5% by 2025 (accounting for 7.2% of GDP)
13. **Diversification of Indian economy**

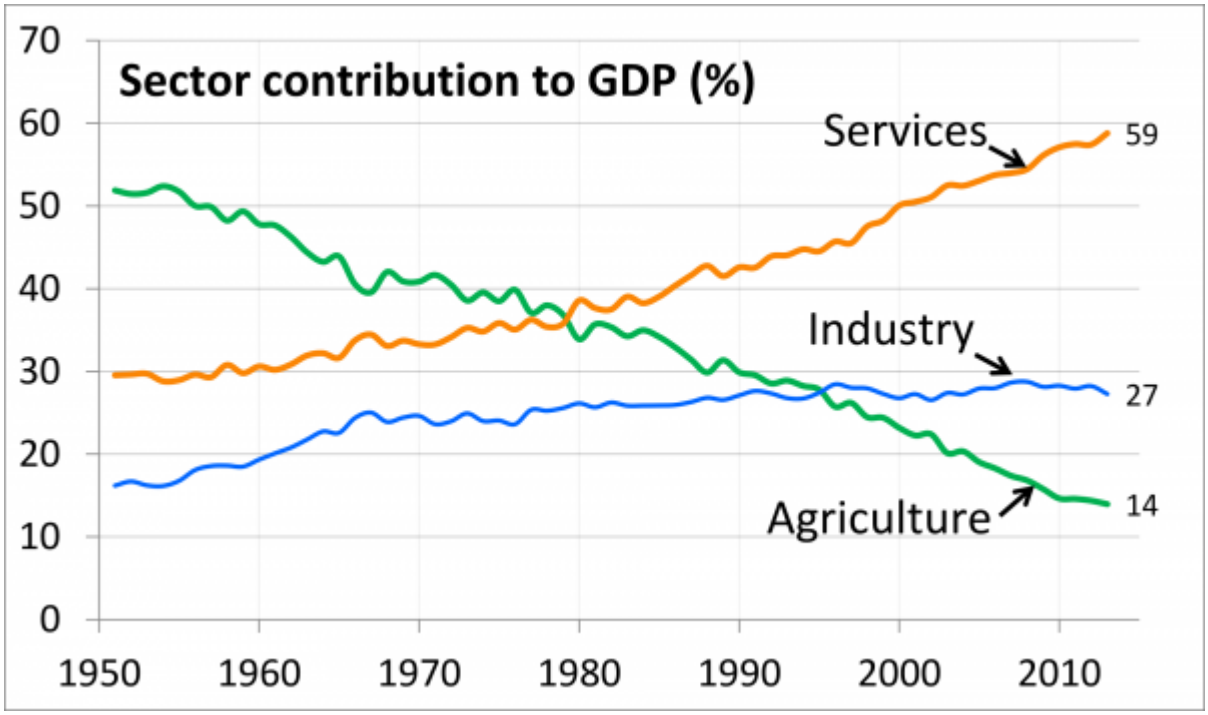

Less dependent on agriculture. Service sector offers a chance for higher economic growth.

PROBLEMS FACING INDIAN ECONOMY

Since 1991, the Indian economy has pursued free market liberalisation, greater openness in trade and increase investment in infrastructure. This helped the Indian economy to achieve a rapid rate of economic growth and economic development. However, the economy still faces various problems and challenges, such as corruption, lack of infrastructure, poverty in rural areas and poor tax collection rates.

1. Unemployment

Despite rapid economic growth, unemployment is still an issue in both rural and urban areas. The fast rate of economic growth has left unskilled workers behind, and they have struggled to find work in growing industries. In 2017, the official unemployment rate was just below 5%. However, a report by the OECD found over 30% of people aged 15-29 in India are not in employment, education or training (NEETs). Livemint reported on March 6, 2017. With, little if any government welfare support for the unemployed, it leads to dire poverty.

2. Poor educational standards

Although India has benefited from a high % of English speakers, (important for call centre industry) there is still high levels of illiteracy amongst the population. It is worse in rural areas and amongst women. Over 50% of Indian women are illiterate. This limits economic development and a more skilled workforce.

3. Poor Infrastructure

Many Indians lack basic amenities lack access to running water. Indian public services are creaking under the strain of bureaucracy and inefficiency. Over 40% of Indian fruit rots before it reaches the market; this is one example of the supply

constraints and inefficiency's facing the Indian economy.

4. Balance of Payments deterioration.

Although India has built up large amounts of foreign currency reserves, the high rates of economic growth have been at the cost of a persistent current account deficit. In late 2012, the current account reached a peak of 6% of GDP. Since then there has been an improvement in the current account. But, the Indian economy has seen imports growth faster than exports. This means India needs to attract capital flows to finance the deficit. Also, the large deficit caused the depreciation in the Rupee between 2012 and 2014. Whilst the deficit remains, there is always the fear of a further devaluation in the Rupee. There is a need to rebalance the economy and improve the competitiveness of exports.

5. High levels of private debt

Buoyed by a property boom the amount of lending in India has grown by 30% in the past year. However, there are concerns about the risk of such loans. If they are dependent on rising property prices it could be problematic. Furthermore, if inflation increases further it may force the RBI to increase interest rates. If interest rates rise substantially it will leave those indebted facing rising interest payments and potentially reducing consumer spending in the future

6. Inequality has risen rather than decreased.

It is hoped that economic growth would help drag the Indian poor above the poverty line. However, so far economic growth has been highly uneven benefiting the skilled and wealthy disproportionately. Many of India's rural poor are yet to receive any tangible benefit from the India's economic growth. More than 78 million homes do not have electricity. 33% (268million) of the population live on less than $1 per day. Furthermore with the spread of television in Indian villages the poor are increasingly aware of the disparity between rich and poor. (3)

7. Large Budget Deficit

India has one of the largest budget deficits in the developing world. Excluding subsidies, it amounts to nearly 8% of GDP. Although it is fallen a little in the past year. It still allows little scope for increasing investment in public services like health and education.

8. Rigid labour Laws

As an example Firms employing more than 100 people cannot fire workers without government permission. The effect of this is to discourage firms from expanding to over 100 people. It also discourages foreign investment. Trades Unions have an important political power base and governments often shy away from tackling potentially politically sensitive labour laws.

9. Inefficient agriculture

Agriculture produces 17.4% of economic output but, over 51% of the work force are employed in agriculture. This is the most inefficient sector of the economy and reform has proved slow.

10. Poor tax collection rates.

According to the Economist, India has one of the poorest tax to GDP rates in the whole world. India's tax revenue as a % of GDP is just 12%. Compared to an EU average of 45%. This poor tax collection rate reflects widespread corruption, tax avoidance and complicated tax rates. In 2017, Narendra Modi has sought to improve tax collection rates and reduce complications through the introduction of a general sales tax (GST) which involves a single tax rate – rather than tax rates applied multiple times at different stages of production. (Modi's tax gamble at Economist)

11. Business difficulties

According to the World Bank, the ease of doing business in India is poor. India ranks 130/190. Big issues for companies include

- Ease of enforcing contracts

- Dealing with construction contracts
- Paying taxes
- Trading across border

12. Inequality within regions

India's economic growth has benefitted some regions more than others. Technological hubs, such as Delhi and Mumbai have attracted higher paying jobs. This has attracted an inflow of most mobile and skilled workers; this has created congestion in these super-cities but failed to address the poverty of rural areas, especially in the north east

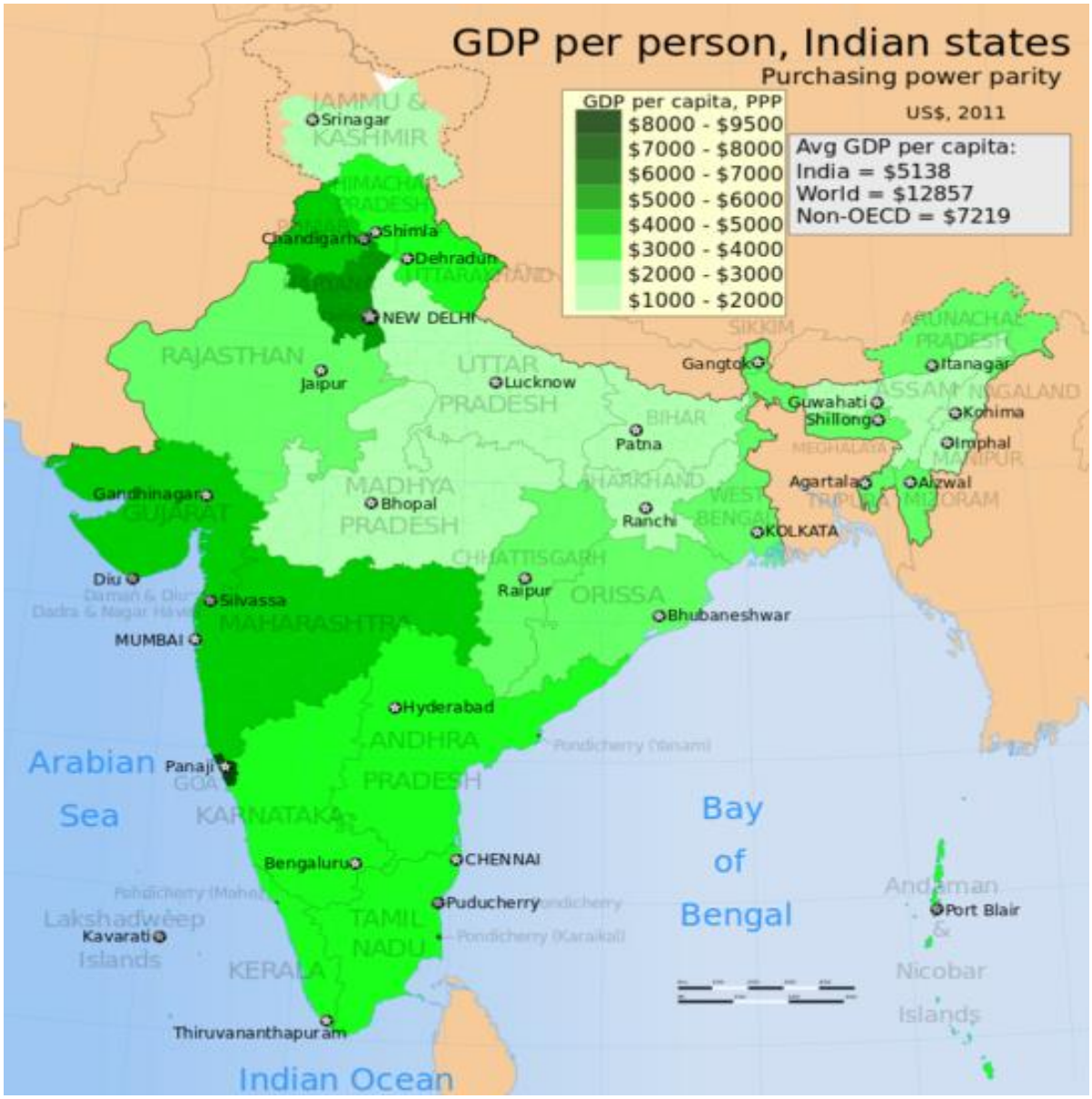

FUTURE PROSPECTS OF INDIA

With the New Year bells ringing, good news is underway for India as its economy is poised to win back its tag of the fastest growing economy in the world. The recent upgrade of India's rating by the US based credit rating agency Moody's (Baa2 from Baa3) in recognition of the reforms agenda pursued by the Government is a major boost to investor confidence. Further, as the short term disruptions

caused by major reforms such as the Goods and Services Tax (GST) and demonetization recede, the economy is on the rebound and is likely to achieve higher growth targets in the New Year.

GDP Growth

Gross Domestic Product (GDP) is on a recovery path after slowdown in the first quarter of 2017-18, and real GDP growth for the second quarter (2017-18) increased to 6.3% from 5.7% in the previous quarter, a likely fallout of the introduction of GST. The second half of 2017-18 will witness a higher growth rate, and this is further expected to consolidate in the coming New Year, as the benefits of GST and other reforms gain traction.

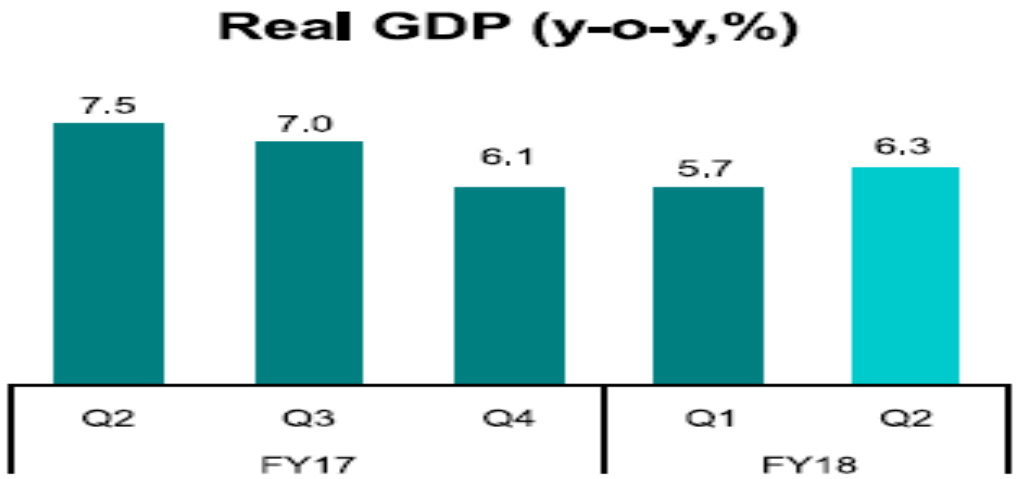

Sectoral Growth

The agricultural sector registered moderate growth as erratic monsoon in several parts and flooding in some states impacted performance.

Industrial growth accelerated sharply during the second quarter of FY 2018 and jumped to 6.9% from 1.5% in the previous quarter, on account of a sharp increase in manufacturing and electricity, gas, water supply and utility services. Manufacturing registered an impressive growth at 7% in 2QFY18 as compared to 1.2% posted in the first quarter.

Services sector grew only marginally at 6.6% in the second quarter as compared to 7.8% in the previous quarter.

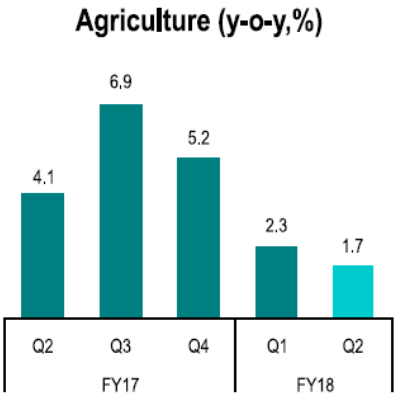

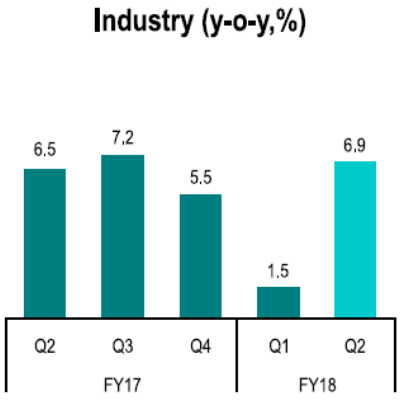

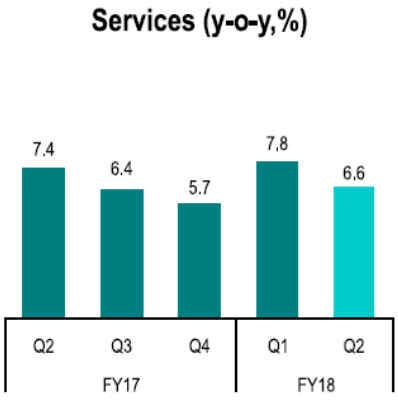

Inflation

The economy saw high inflation during October 2017 owing to elevated food prices. Going forward, this is likely to be contained on account of a good harvest and favourable monsoons.

The impact of GST on prices is likely to become clearer in the coming year as the teething problems related to its implementation ease out. Further, the GST Council's decision to cut tax rates on 177 items is also expected to partially ease the inflationary pressure, as the companies start passing the benefits of lower prices to consumers.

External Sector

Healthy foreign fund inflows caused the rupee to strengthen during the latter half of the year. The recent Moody's upgrade is likely to encourage further inflows and the rupee could appreciate further. On the other hand, the impact of the decision in the US to raise interest rates and introduce tax cuts may work the other way. In any case, India's consumer markets are expected to remain a strong incentive to FDI.

A contraction in export growth pushed the merchandise trade deficit to a near 3-year high in October 2017, which was forcefully reversed in November with a positive growth rate of over 30%. With the streamlining of GST related issues and some changes in GST rules by the Government as well as firming of global recovery, export growth will emerge as a powerful growth driver in 2018.

Monetary Policy

The Reserve Bank of India (RBI) kept policy rates unchanged in its fifth bi-monthly monetary policy meeting on 6thDecember, 2017. However, industry is hopeful that going forward, RBI would lower interest rates to boost broad-based investment and consumption activity which in turn would promote economic growth.

Credit Growth

Credit growth to the non-food sector shows encouraging signs of pick-up in the last few months. Recapitalization of Public Sector Banks may bolster credit flows further and ease their stressed assets situation.

CII Business Confidence Index

The Business Confidence Index (BCI) by Confederation of Indian Industry (CII), climbed up to 59.7 during October-December 2017 as against 58.3 in the previous quarter. This increase was a result of improvement in the perception regarding overall economic conditions and expectations of improved business situation post the recent disruptions which prompted companies to be optimistic about favourable economic growth in the future. The findings are part of CII's 101stedition of quarterly Business Outlook Survey, based on around 200 responses from large, medium, small and micro firms, covering all regions of the country.

The recovery recorded in the index coupled with India's sharp improvement in the Ease of Doing Business rankings (India jumped 30 places to 100) this year reinforces company perception that demand pick up is underway. Most of the respondents in the survey also believe that GST payments would become hassle-free by Q1 2018-19.

Challenges

Firms rated low domestic demand followed by high commodity prices as main concerns in CII's Business Outlook Survey. Stepping up private investment remains a major macroeconomic challenge in the next year.

Inflationary pressures also remain a concern. Though food prices are likely to be contained on account of favourable monsoons, caution must be exercised as upside risks still remain in the form of implementation of farm loan waiver and 7th Pay Commission hand-outs.

India's share in world exports is currently at 1.8%. Efforts to increase this figure by way of providing export credit to manufacturers, increasing the capital base of Export Credit Guarantee Scheme (ECGC), increasing subvention to 4% etc. must be undertaken.

The economy benefitted from increased foreign inflows during the latter half of 2017. While this is good news, efforts to contain further appreciation of the rupee should be in place as further strengthening may affect exports and job creation.

Bank credit growth hit a 20 year low in 2016-17 with Non-Performing Assets (NPAs) at 9.9%. India has been ranked fifth on the list of countries with highest NPAs. Though bank recapitalization efforts are underway, the economy needs to recover from the bad loan problem quickly for favourable economic growth in the future.

The infrastructure deficit is a major concern and infrastructure investment needs to be stepped up as currently it is not in par with the needs of the economy.

Other challenges for the economy include addressing infrastructural bottlenecks in the agricultural sector, investment in human resources to leverage the demographic dividend, increasing expenditure on education and healthcare sectors, and social security provision for the unorganized sector.

With on-going reforms that are beginning to positively impact the economy, CII is optimistic about Indian growth prospects in 2018. At the same time, policymakers need to be watchful and address the current macroeconomic challenges for a sustainable and fruitful recovery.

CONCLUSION : The Indian economy is one of the fastest growing economies in the world today. The rising income and savings levels, investment opportunities, huge domestic consumption and younger population will ensure growth for decades to come. The main engines of Indian economy are sectors such as Information Technology, Telecommunications, ITES, Pharmaceuticals, Banking, Insurance, Light Engineering Goods, Auto Components, Textiles & Apparels, Steel, Machine Tools and Gems & Jewellery are sectors which are likely to grow at rapid pace world over creating demand for Indian products and services. India is at present US$ 4.5 trillion economy on PPP basis and is likely to maintain its growth trajectory in times to come. The coming few decades are likely to witness tectonic shift in world economic structure of the world. India‟s share in world output is projected to jump from 5% as of today to 20.8% by 2040 as per one estimate.

World Economy: Future Economic Power Shifts (2008-2040)

	2008	2014	2020	2030	2040
GERMANY	4.2	3.8	3.4	2.8	2.3
USA	20.4	19.2	17.6	15.3	13.9
JAPAN	6.2	5.6	4.7	3.7	2.9
CHINA	11.3	16.3	22.2	30.9	37.4
INDIA	4.9	6.3	8.5	14.3	20.8

REFERENCES :

Indian Economy Since Independence by Uma Kapila.
Indian Economy : Performance and Policies by Uma Kapila.
https://www.economicshelp.org/india/problems-indian-economy/
https://www.ciiblog.in/indian-economy-in-2018-current-status-prospects-and-challenges/
http://cgijeddah.mkcl.org/WebFiles/History-of-Indian-Economy.pdf

किसान एवं कृषि विकास

SHIVANI SHUKLA
M.Phil (Commerce) APSU University Rewa

प्रस्तावना : मध्यप्रदेश मुख्य रुप से एक कृषि राज्य है। राज्य की लगभग 73% जनसंख्या ग्रामीण है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कृषि पर निर्भर करती है।
इस प्रकार कृषि क्षेत्र राज्य अर्थव्यवस्था का मुख्य स्थान है। किसान कल्याण विभाग और कृषि विकास विभिन्न राज्यो और राष्ट्रीय प्रयोजित योजनाओं जैसे :– कि कृषि विस्तार कार्यक्रम, उर्वरक गुण्वत्ता नियत्रंण कार्यक्रम भू जल के सवंर्धन एकीकृत कीट प्रबंधन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ आदि का चलाते है।

शोध प्रविधि :– किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यो की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अनवेषण या जॉच – पड़ताल को अनुसंधान कहा जाता है।
अनुसंधान के अंतर्गत समग्र के विषय में जानकारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त की जा सकती है। इस शोध – प्रविधि में द्वितीयक समंको का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है।

परिकल्पना : समस्या से सबंधित समस्त तथ्यों को आसानी से एकत्रित नही किया जा सकता अतः उसके लिए शोधर्थो अपने में एक रुप रेखा बना लेता है। प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पना को लेकर आगें बढ़ने का प्रयास किया गया है।

समस्याये एवं कठिनाईयॉ :– किसानो की सबसे बडी समस्या है उनकी कृषि का विकास ठीक प्रकार से न हो पाना और अन्य समस्याये इस प्रकार से है–

1. **किसानो की लागत का बढना** :– पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाको में किसानो की लागत में बहुत तेजी से बढोत्तरी हुई है, इससे सबसे अधिक बढोत्तरी सिचाईं सुविधाओ पर होने वाले खर्च में ही है।
2. **मुश्किल में किसान** :– बडी तादाद में ऐसे किसान है जिनकी जोत दो एकड या इससे भी कम है। लेकिन उनको दो साल से गन्ना मूल्य का आंशिक भुगतान ही – हो सका है।
3. **फसलों की कीमते गिरी**:– पिछले एक साल में अधिकांश भारी गिरावट दर्ज की गई नतीजतन किसानों की आय कम हुई है। लेकिन उनकी आमदनी में इजाफा करने का कोई बडा कदम सरकार ने नही उठाया है।

सुझाव : प्रस्तुत शोध अध्ययन किसान एवं कृषि विकास के सामाजिकरण की नवस्थिति विवेचना पर केन्द्रित है।–

1. श्रम कानूनो में संशोधन।
2. स्वास्थ्य, शिक्षा एवं दीक्षा जैसी योजनाओ का सफल कार्यान्वयन।
3. किसान निर्धारण में स्त्री–पुरुष भेदभाव का अंत।
4. श्रम, धन जैसी अन्य योजनाओं की शुरुआत।
5. असंगठित किसानो के प्रति पुलिस एवं प्रशासन के रवैयें में परिवर्तन के लिए ठोस प्रयास।

निष्कर्ष :– बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी उन्मूलन आदि, ऐसे निष्कर्ष निकलते है। वर्तमान हरियाणा सरकार ने तीन वर्ष पहले 'ाासन की बागडोर सभाली थी। हमारा लक्ष्य सभी को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। हरियाणा में मजदूरो की कमी है, इसलिए हमारे उद्यागो में काम करने के लिए बहुत से प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश की ओर आर्कषित हो जाते है।

संदर्भ – ग्रन्थ :

1. मध्य प्रदेश रोजगार और निर्माण 19/03/2018 से 25/03/2018 पेज नं. 25
2. विकीपीडियॉ
3. S.N. Mishra labour and industrial laws . P. 10

Financial Innovation in Economy

Anubha Chaturvedi
Research Scholar, Department of Economics, University of Allahabad, Allahabad

Abstract :- Financial Innovation which can be categories as the terminology used in the economic and financial development of the country. Financial Innovation is process to provide procedure of the economic development by increase in GDP. The process to provide the procedure can be explained as to give a path to countrymen by support ethically, morally and technically. This path can be taken as to develop the root map of having an environment to start producing goods and services. And the environment can be taken place by dissemination of the information smoothly and efficacy. For Example India's Prime Minister Shri Narendra Modi "Man Ki Baat" which can be taken as Moral and Ethical. Same things were also observed during the speech of former U.S. President Mr. Barak Obama regarding ethics, motivation and morality. For technical support there could be several training program, certification course or specialized degree course to make an entrepreneur. For example Skill Development program of Indian Government. The Financial Innovation is the system which can be created by disseminating the information and awareness. To make aware the countrymen about new concept and innovation there should be effective way of communication which can be only possible with uniform platform of information source. For example mobile data internet is the very useful tool to spread the information and awareness, In this context India has great revolution where the digitalization taking place. Several mobile data internet companies are offering internet at a lower cost which is helping the population living at villages to avail and be the part of the digitalized India. With the help of digitalization which is a platform for Financial Innovation to make countrymen ethically, morally and technically equipped to contribute in GDP. By the Financial Innovation if we are able to create the new system by disseminating information and training efficacy the economy could be at new heights.

Key words :- good, services, innovation, sustainable development, ethical, moral, technical, efficacy.

Introduction :- Financial Innovation is not only just two words but also the its comprising to create way and path by having ethical, moral and technical knowledge to use them by innovating the new product and services.

1. The New Product Development required by new financial system.
2. The New Services Development required by new financial system.

To discuss the historical back ground of the Financial System we have to remind ourselves the barter system when a goods and services are to be exchanged with each other. Then currency came into the existence post which credit and banking came into the picture. But now we are into the age of the new innovation era which can be identified as "financial innovation". In the past there was no trend to explain the goods, services and capital market separately but here I would like to discuss in the Financial Innovation which is include that countrymen will produce the goods, services but when a person having equity and bonds which is indirectly going to be the part of producing goods and services should also recognize. In the financial innovation we can take challenge to make country and economy in developed state by having the higher GDP and this can be efficacy possible by Financial Innovation. Means when an individual and non-individual is

going buy an equity the movement they possess the shares of that institution they will be the part of producer of goods and services. For the debt funds investment an individual and non-individual park their funds at the at certain rate of return for a specific period of time is also going to some of the production concern like goods and services production.

The financial system can be assumed as the adopted new economic system of the country which includes:

- Equity Market
- Debt Market
- Goods Market
- Service Market

As concerned with all above markets which are covering all the markets of the Economy and Country. To give the boost and control these markets we need to have some Techniques, Procedure and Theory which can be elaborated as "Financial Innovation ". This Financial Innovation can give the path to an economy and country to have higher GDP and Foreign Reserves by Exporting the Goods and Services.

Objective :-

- To identify what should be the shape of financial innovation.
- To identify what can be the target markets for financial innovation.

Research Methodology :- Total paper is designed on the secondary data available from various sources, cases, reports, white papers.

The shape of the Financial Innovation :- In The Economics terminology there are few terms which can the parts of the Financial.

innovation includes :-

- New Adopted Change in the Environment- Financial and Economic
- To identify Target market
- Human Behavior – A required research to be conducted

These are pillars of Financial Innovation Research, we have to discuss these in details which will help us to have the better context of Financial Innovations to be needed.

New Adopted Change in the Environment - Financial and Economic :- The changes are the nature of law and adoption of new changes are the symbol to way forward, As the Economy is every time required the good rate of return to have sustainable development of the country. Every economy have to create a positive economic and financial environment by the way of certain rules and regulations:

- Tax Reform.
- New Industry Setup Subsidy.
- New Kind of Market development for a specific Goods & Services.
- What are the new habits adopted by the consumer.
- Private Industries to be promoted.

These are the few points to be elaborated for the detail discussion on the environment of economic and financial. If an Economy start focusing on these, there are the chances to grow like anything because so many economic theories say economy wants big Push and a healthy competition within and environment.

To identify Target market :

Equity Market :- The equity market of the economy is something which includes all the trade and investment. This market is itself a kind of way to contribute in the economy by investing the capital to gain on equity. In the financial Innovation we can have the equity market as an opportunity to be the part of GDP by an individual on non-individual.

The ways to invest in equity could be :

- Investing in shares of the Ltd Companies.
- Investing in shares of the Government Companies.
- Investing in shares of Pvt. ltd companies.

The above are the ways to invest in equity or to place a capital of individual or non-individual which is directly proportionate to produce the goods and services by which the GDP can go on higher side.

Debt Market :- This is the market in which we can say the fixed returns investments are taken place like FDR, BONDS, GOVERNMENT SECURITY and Debentures. In this market an individual or non-individual are keeping their money for a tenure to get the fixed returns. The objective of this kind returns are also contribute in GDP by investing further on different sectors.

Goods Market :- In the financial Innovation we are having huge to discuss about the goods market. This market covers approx. 80% of the total market in which we can have need of financial Innovation. This market include all tangible from small particle to world's large particles goods which are marketed by individual or non-individual.

This market includes industries:

- Oil and natural gas
- Food grain
- Clothing's
- Flowers
- Heavy Vehicle, all vehicles
- Toys
- Housing
- Etc.…

Many more which are involved in production of tangible goods. These are the market to utilize the resources of country for sustainable economic development.

Services Market :- These are the market for intangible service which are to be marketed by the people of country.

This market includes :-

- Hotel and Hospitality
- Tourism
- Health
- Education
- Sanitation
- Many more can be included related to the services

Conclusion :- To conclude I would like to highlight that we are in the era of things moving automatically by old perception and experience without an introduction of new economic challenge and prospect. As the sustainable development is an essential requirement by any of the country and the sustainable development can take place with higher GDP growth and this growth can be taken place only by the Financial Innovation of Economy.

As the goods can be produced by a countrymen by their ability to make and services can be produced by specialist who learn things by an institution. If countrymen are fully aware about what they have to do to earn their bread and afterwards how they can do contribution in the country's GDP it definitely possible to make a country developed from under developed and developing.

We have certain qualities and positive environment in Indian people which can help in this financial innovations direction. This Financial Innovation can only shape the plans and strategies already in place in the current economic system.

References :-

- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2894973

- Financial Services Technology 2020and Beyond: Embracing disruption, PwC Report,
- The Impact of Electronic Payments on Economic Growth, Moody's Analytics, 2015
- Top 10 Payment Trends in 2016, Capgemini Financial Services Analysis Report, 2016
- Mehrotra A, Yetman J (2014) Financial Inclusion and Optimal Monetary Policy, Bank of
- International Settlements Working paper no. 476, BIS
- Oxford Policy Management Ltd (2011) Enhancing Financial innovation & Access, "Evaluation
- of Agent Banking Models in different countries". www.efina.org.ng

योग संस्कृत समाज की आत्मा

डॉ. मनोज कुमार शर्मा
पी. एच. डी. योग विभाग

हमारे देश में आदि काल से ही संस्कृति का मूल्य सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में मनुष्य बनने की अवधारणा निहित है। मनुष्य जाति में जन्म लेना ही मनुष्य नहीं कहलाता अपितु मनुष्य के हृदय में सत्य, परोपकार, अहिंसा, आन्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की शिक्षा के लिए वैदिक शास्त्रों का अभिउदय हुआ है। मानव जीवन में आध्यात्म की अनुभूति को पुरूषार्थ चतुर्पटम में आधार स्थान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण विषय स्थापित किया गया है। क्योंकि धर्म के बिना अर्थ अनर्थ का कारण बनता है और अंतहीन कामना की आग में जीव जीवन भर जलता रहता है। जबकि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। जो पुरूषार्थ चतुर्पटम का अंतिम सोपान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मातसर्प से युक्त जीव अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और वह उससे वंचित रह जाता है। यदि मानव योनी में जन्म लेकर भी मनुष्य, मनुष्य नहीं बन पाता बल्कि पशु तुल्य जीवन यापन करता है। क्योंकि उसके जीवन में न विद्या, न तप, न दान, न ज्ञान, न शील, न धर्म है ऐसा मनुष्य मृत्युलोक में अनेकों बार जन्म लेकर मृग तृष्णा की भांति जीवन व्यतीत करता है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति देहात्म में से आत्मा की खोज करते हुए एकात्म मानव दर्शन की संस्कृति है। जहां व्यक्ति व्यष्टि चेतना से ऊपर उठकर समष्टि चेतना का साक्षात्कार कर वसुधैव कुटुम्बकम का दर्शन करता हमारी संस्कृति किसी विशिष्ट देश धर्म या समुदाय की भलाई से संबंधित न होकर समस्त विश्व की मानव जाति की कल्याण से सम्बद्ध है। श्रुति वाक्य सर्व अविलम, सर्व स्वविदम ब्राम्ह की दृष्टि के कटे जगत को अपने में और अपने को सारे जगत में दर्शन कराने का भाव ही भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति होने का अवसर प्रदान करती है। संस्कृति समाज की आत्मा है यह कटु सत्य है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है उसी प्रकार संस्कृति के बिना समाज का कोई महत्व नहीं हो सकता जब तक संस्कृति जीवंत है तभी तक समाज सजग एवं प्रबल हो सकता है क्योंकि किसी भी समाज में उसकी संस्कृति के ही दर्शन होते हैं और संस्कृति की जननी संस्कारों को ही माना गया है। यह सत्य है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता मानव की प्राकृतिक व जन्मजात प्रवृति है और इसी प्रवृति का निर्माण भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति के विकास क्रम में सबसे विकसित जीव मानव है। यही इसके एकात्म मानव दर्शन की संस्कृति का विकास नहीं हुआ तो प्रकृति के विनाश में दानव की भूमिका भी भारतीय संस्कृति विहीन मानव द्वारा सृजित की जाएगी। जहाँ तक मानव में प्रकृति तक सीमित रहेगा वह मनुष्य विकास में सहभागी नहीं हो सकता वरन् प्रकृति के विनाश में सहभागी होगा। लेकिन आत्म मय को प्राप्त मनुष्य ही श्रेष्ठ प्राणी की भूमिका निभा सकता है। जिसका भाव समाज के हर जीव के लिए सभी सुखी रहें सभी निरोगी रहें, सभी अच्छे दिखें किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो यह मानव का शब्द नहीं आत्म अनुभूति के पश्चात स्वतः स्फूर्त वाणी हो जो संसार में अपने को और संसार को अपने में देखता है। ऐसा मनिषी का निर्माण भी भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। वेदों में जन्म से मृत्यु के मध्य जितनी भी समस्यायें हैं उन सब का समाधान भारतीय संस्कृति में संस्कार और सत्संग एवं यौगिक पथ के अनुगमन से होता है। वह समस्या चाहें वैचारिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो या दार्शनिक हो इन सभी के सम्बन्ध में वेद का अपना विशिष्ट संदेश एवं आदेश है। वेदों में जिस समाज की संरचना का या समाज दर्शन का चमत्कृत ज्ञान उपलब्ध होता है। वह विश्व के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। वह एक ऐसी आदर्श समाज की स्थापना है। सम्भवतः ऐसी उच्च सामाजिक संरचना होनी अपेक्षित है।

वेद मनुष्य की व्यक्तिक, आर्थिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं पर चिंतन करते हैं वैदिक संस्कृति में समाज व्यवस्था के रूप में आत्म व्यवस्था सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन साध्यों के रूप में पुरूषार्थ चतुर्ष्य व्यक्ति के जीवन को सुसंस्कृत करने में सहायक सिद्ध होगी इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संस्कृति की मानवीय समाज को अमूल्य देना है। संस्कृति का उद्देश्य मानव समाज की प्रत्येक जन की शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है क्योंकि व्यक्ति सब प्रकार से उन्नत हों यदि सामाजिक व्यवस्था का परम उद्देश्य है इसलिये भारतीय संस्कृति में व्यक्ति की उन्नति के लिए सामाजिक संरचना का मूल आधार वर्ण व्यवस्था है।

यह व्यवस्था पुरातन भारतीय समाज एवं संस्कृति आधार स्तंभ हों सभ्यता और संस्कृति तथा व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सम्पूर्ण समाज का चर्तुमुखी समन्वित विकास करना और मानव व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाना ही वर्णाश्रम धर्म का परम अभिष्ठ है।

यत्पिण्डे तद्ब्रम्हा के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर वैदिक संस्कृति में शरीर को ही सामाजिक संगठन का आधार बना कर शरीर अवयवों के स्वाभाविक कार्य के अनुकूल समाज को चार हिस्सों में बाँटा गया।

ब्रह्मणोअस्य मुखमासीद वाहू राज्न्यः कृतः।
उरूतदस्य यद्वेश्यः पदम्यों शुद्रोअजयत।। (यजुर्वेद 31/11)

अर्थात उस समाज रूपी पुरूष का मुख ब्राह्मण उस की भुजाओं के रूप में क्षत्रिय उस की जंघाओं के रूप में वैश्य और पैर के रूप में शूद्र हुए हैं परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सबसे उत्तम (विद्या, ज्ञान, तप एवं त्याग) गुणों का धनी ब्राह्मण है जिसमें बल अधिक है वह भुजा के तुल्य समाज का रक्षक है वह क्षत्रिय है। सम्पूर्ण पदार्थों की प्राप्ति करने वाला एवं समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने वाला गुरू सदृश्य वैश्य है। किन्तु जो सम्पूर्ण समाज का भारवाहन कर सेवा भाव में सदा लगा रहने वाला द्विज आदि का आधार रूप शूद्र, पाट, स्थापित है। वहीं स्वामी दयानन्द ने इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ण आधारित समाज व्यवस्था को गुण कर्म अनुसार जिसका वर्णन किया जाए तथा गुण कर्म स्वभाव को देखकर यथा योग्य जिस कार्य का अधिकार दिया जाए वह वर्ण है। अर्थात वर्ण वह है जिसे व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार करता है। इसी को श्रीमद्भगवतगीता में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या में कहा कि गुण कर्म के आधार पर ही समाज में वर्ण व्यवस्था की गई हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर यह है कि वर्ण का निर्धारण गुण और कर्म के आधार पर होता है और जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। भारत की संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र इन चार वर्णों की सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत योग्यता अभिरूचि और क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत की गई है। जो वर्तमान समय में जाति व्यवस्था का रूप लेकर निंदा का विषय बना हुआ है।

स्वामी दयानन्द ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में चतुर्र वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है कि जो शूद्र कूल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य कूल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश्य हों तो वह शूद्र हो जाए उसी प्रकार क्षत्रीय, वैश्य के कूल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण और शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात कर्म ओर स्वभाव तथा गुणों के अनुसार किसी भी जाति में कोई भी स्त्री पुरूष जन्म ले वह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसी वर्ण में गिना जाना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रकृति के अनुसार उत्पन्न गुण सत, रज, तम के अनुसार अपनी मानसिक प्रवृतियों के कारण चार प्रकार के होते हैं इन्हीं चार प्रकार के व्यक्तियों के अनुसार वर्ण आश्रम भी चार प्रकार के बताये गये हैं। सात्विकता प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण तथा सात्विक राजसिक व्यक्ति क्षत्रिय राजसिक व तापसिक व्यक्ति वैश्य और तापसिक प्रधान व्यक्ति शूद्र माना गया है। इन चार वर्णों के अधीन व्यक्तियों का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम पर आधारित है। भारतीय संस्कृति की यह वर्ण व्यवस्था शोषण मुक्त विषमता रहित व्यक्ति के पूर्ण विकास की सम्भावना से उक्त हूँ। जिसमें व्यक्ति अपनी रूचि योग्यता तथा गुण कर्म स्वभाव के अनुसार किसी भी वर्ण को धारण कर सकता है। यह वर्ण व्यवस्था आधुनिक समाजवाद से श्रेष्ठ व्यवस्था है। हमारे भारतीय मनीषियों के चिंतन के अनुसार व्यक्ति के चार पुरूषार्थ हैं और इन्हीं की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए मानव शरीर बडे भाग्य से जो देवताओं के दुर्लभ है मिला है पुरूषार्थ के रूप में प्रथम धर्म, द्वितीय अर्थ तृतीय काम और चतुर्थ मोक्ष को बताया गया है। मानव को जीवन में पुरूषार्थ करके इन्हीं चारों को सिद्धी करना है और इन चारों पुरूषार्थों की सिद्धी प्राप्त करने के लिए चार आश्रम का भी निर्धारण हमारे मनीषियों ने किया है। यथा ब्रम्हचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि मनुष्य को उचित है कि वह ब्रम्हचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर उसका सफलता पूर्वक निर्वहन करें, पश्चात वानप्रस्थ आश्रम धारण करने पर समाज का मार्ग दर्शक रहते हुए इस आश्रम को भलीभाँति निभा कर चतुर्थ आश्रम के रूप में सन्यास को धारण कर सम्पूर्ण सृष्टि को जड़ चेतन में नारायण के दर्शन करें।

आश्रम को परिभाषित करते हुए महर्षि दयानन्द ने भी कहा है कि जिनमें अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किये जाए उनको आश्रम कहा जाए। आश्रम व्यवस्था सम्पूर्ण व्यक्तित्व जीवन को एक सूत्र में पिरोने की पद्धति है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन विशुद्ध, योग्य परोपकारी, मंगलमय एवं उपयोगी बनाया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव जीवन को इन चार आश्रमों में विभाजित किया गया है। इन समस्त संस्कार व संस्कृति का उदय योग विद्या से हुआ जिस की शिक्षा में यम के उपांग के रूप में ब्रम्हचर्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके साधक को ब्रम्ह के बताए मार्ग का अनुशरण करना है। ब्रम्ह का मार्ग संयम सदाचार इन्द्रिय निग्रह और मन पर नियंत्रण कर विचार सदा रहना यह प्रथम आश्रम है इसी के अधीन विद्या अध्ययन के साथ शरीर की सौष्ठता मन पर नियंत्रण श्वान जैसी निद्रा काम चेष्ठा वक के सदृश ध्यान अल्प आहार और ग्रह के लिए निश्चिंतता के साथ ओज का

संग्रह इसके पश्चात बल और वीर्य के संग्रह के साथ ही गृहस्थ जीवन के 25 वर्ष पूर्ण कर आश्रम में प्रवेश कर पाणिग्रहण का आनन्द लेकर साधक मन वचन कर्म से संतति में वृ0 कर समाज का सोहार्द ग्रहण कर समाज हित के कर्म करना परिवार के भरणपोषण के दायित्व का निर्वहन करने हुए कृषि, उपासना, परोपकारिकता, सत्यता, दान, श्रम से वैदिक समाज सुपरिचित था इस बात के भी संकेत मिलते हैं अथर्ववेद में भी यज्ञ, इस गृहस्थ आश्रम के प्रमुख लक्षण हैं। यजुर्वेद में इस आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अन्य आश्रमों का आश्रय प्रदाता है। अर्थात भरण पोषण का दायित्व इसी आश्रम पर है शेष तीनों आश्रमों का मूलाधार है इसी की आयु सीमा 25 से 50 वर्ष निर्धारित है। जीवन का तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है जिसे आयु सीमा 50 से 75 वर्ष है। साधक को वन में प्रस्थान करने के कारण ही वानप्रस्थ शब्द निर्मित हुआ है। इस अवस्था में बाल सफेद त्वचा शिथिल होने के साथ ही पत्नि को बच्चों के पास सौंपकर वनगमन करना या समाज का मार्ग दर्शन या अपने अनुभव को त्याग देना इस आश्रम में तपस्या सत्संग चिंतन आदि के माध्यम से ज्ञान युक्त पवित्रता का नित्य अर्जित करना तथा उसे समाज को दान करना मुडकोपनिषद के अनुसार इस आश्रम में व्यक्ति संयम तपस्या धर्माचरण व उत्तम परिष्कार करता हुआ जीवन के परम साधना मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना इसके पश्चात जीवन का अंतिम आश्रम सन्यास यह चतुर्थ आश्रम है इस की आयु सीमा 75 से 100 वर्ष मान्य है। महर्षि दयानन्द ने कहा है कि सच्चा संयासी वही है जो संयम व समाज को सत्य व धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। सतपथ ब्राह्मण में सन्यासी के लिए पुत्रेषणा, विनतेषणा और लोकेषणा का त्याग कर निष्ठा चरण करते रहने का आदेश है। साथ ही मोह का त्याग कर मोक्ष के साधको में तत्पर रहते हैं। समाज को सत्योपदेश के साथ विद्यादान ही मुख्य रूप से सन्यासी का कार्य है। वह स्थान ब्रम्ह में स्थित होकर अग्रित पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे शब्द की संस्कृति सर्वधर्म समभाव की है। यहां अनेकता में ही एकता के दर्शन होते हैं। समस्त योग का भाव ही यह है कि मन वचन व कर्म से सम अवस्था में सदैव संतुष्ट प्रसन्न रहना योग का शाब्दिक अर्थ भी जोडना है। इसलिए भगवान हिरण्य गर्भ ने जब योग को उपदेशित किया कि अण्डज पिण्डज स्वदेज उर्मज यह चार प्रकार से जीव की उन्पत्ति का विधान है और जलचर थलचर नभचरों की चौरासी लाख यौनियां हैं लेकिन हठ योग के प्रथम अंग आसन का प्रश्न है तो जिसकी भी योनियां हैं आसनों की संख्या भी उतनी ही है साथ ही हठ योग के द्वितीय अंग प्राण की आवश्यकता प्रत्येक जीव को रहती है। चाहे वह किसी भी रूप में प्रकट हुआ है तब यह सत्य है कि योग जीवन जीने की कला का नाम है। गर्भ से लेकर शरीर के अवसान तक योग विद्या साथ रहती है। मानव का धर्म उस का स्वभाव है मूल स्वभाव परोपकार व सत्य का है जिसके परिणाम में शांति व प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यह शरीर जिन पंचतत्वों से निर्मित है। उन सभी का गुण और स्वभाव अपना अपना है। आकाश तत्व का गुण शब्द है। स्वभाव शांति है नाद ही ब्रम्ह की पहचान है इसलिए ॐ को प्रणवाक्षर के नाम से जाना जाता है। वायु का गुण स्पर्श व धर्म प्राण की निरंतरता अर्थात बहना या गति है। गति चैतन्यता की सूचक है बिना गति के जडता का उदय होता है। अतः गति विहीन पदार्थ मृत हैं।इसी प्रकार अभिन्न तत्व का गुण दाहकता है स्वभाव प्रकाश है। प्रकाश ही जीवन है। अन्धकार ही मृत्यु है। इसी लिए ऋषियों ने कहा कि तमसो मा ज्योतिर्गमय इसी क्रम में चतुर्थ तत्व जल जिस के बिना जीवन सम्भव नहीं है का गुण रस है। स्वभाव तरलता है। कार्य गीला करना है और पंचतत्वों में अंतिम तत्व पृथ्वी है जो सभी तत्वों से सम्पन्न है का गुण गंध है। स्वभाव सहनशीलता है इन विभिन्न गुण धर्मों स्वभाव से युक्त यह मानव शरीर जो समाज का अंग है जिस के उदय से अन्त तक कितने परिवर्तन हैं। फिर भी ऋषियों के दिये संदेश को हम संस्कृति के रूप में अपने कार्य व्यवहार व विचारों में लेकर चलते हैं। जिसके कारण ही हमारा देश विश्व गुरू के रूप में देखा जाता है। यहां की संस्कृति ही विश्व में पहचान की जाती है। इसीलिए हम संस्कृति को समाज की आत्मा के नाम से जानते हैं। क्योंकि समाज में जिसका अस्तित्व नहीं वह शरीर से जीवित होने के बाद भी मृत है क्योंकि जिसके पास चरित्र नहीं संस्कार नहीं वह मृत है। जब कि हमारी संस्कृति युगों–युगों से सदमार्ग पर चलना, सत्संग करना, सत्य का आचरण करना, सात्विक वृद्धि रखना सहज और शांति रहना एवं आत्म अवलोकन करना ही सिखाती है जो कर्म की पूर्णमा ज्ञान कराती है वह संस्कृति है। यह वास्तविक रूप से हमारी जीवन की विधि है हमारा रहन सहन आचार विचार व्यवहार ये सभी संस्कृति के पक्ष हैं संस्कृति हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। यह भी सत्य है कि मानवों की सभी उपलब्धियां यथा कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म विज्ञान ये सभी संस्कृति के पक्ष हैं और संस्कृति में हमारे रीति–रिवाज, परम्परायें, पर्व व जीवन जीने की तरीके आदि पर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है लेकिन मानव जनित संस्कृति पर्यावरण का भी ध्यान रखती है जिस पर व्यक्तियों की सामान्य सहमति है क्योंकि संस्कृति का मूल केन्द्र बिन्दू मानव के सूक्ष्म विचारों में निहित है। वास्तविक रूप से संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है जिस का दर्शन हमारे प्रत्येक में होता है। हमारी संस्कृति पश्चिम से भिन्न है। हमारी संस्कृति में धार्मिक विश्वास प्राप्त वचनों का सम्मान आदि संस्कृति के दो पक्ष हैं अधिभौतिक संस्कृति तथा भौतिक संस्कृति को सभ्यता के रूप में जाना जाता है।

संस्कृति की विवेचना हमारे आदि कवि कालिदास जिन्हें हम भारत के शेक्सपीयर के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने विषद ज्ञान की रश्मि सम्पूर्ण राष्ट्र को दी है वहीं कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर, वंकिमचन्द्र, ईश्वर चन्द विद्यासागर जैसे मनीषी युग पुरूषों ने समाज सुसंस्कृति का परिचय कराया है।

संदर्भित ग्रंथ :–

रामचरित मानस	–	गीता प्रेस, गोरखपुर
हठ प्रदोषिका	–	स्वा0 सत्यानन्द
घेरेण्य संहिता	–	स्वा0 निरंजनानन्द
यजुर्वेद	–	गायत्री शक्ति पीठ हरिद्वार
भारतीय दर्शन	–	प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा

मंडला जिले में आदिवासी नारी शिक्षा : आजादी के पहले और आजादी के बाद

डॉ. मनीष कुमार दुबे

प्राचीन काल में ही भारतीय महिलाओं का समाज में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान रहा है। भारतीय धर्म और संस्कृति में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। **'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता'** यदि इतिहास पर नजर डालें तो मध्ययुगीन काल से लेकर आज तक लिंगभेद में कोई आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आज के समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो पिछड़ापन जगजाहिर है, मानव सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही भारतवर्ष अपनी शिक्षा तथा धर्म के माध्यम से दर्शन प्रदर्शन के माध्यम से पूरे विश्व का पथ प्रदर्शक रहा है लेकिन वर्तमान में हमारी शिक्षा दिशा विहीन होती जा रही है। नारी शिक्षा के प्रति भेदभाव बरकरार है तथा नारी शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास में सहायक होने के साथ ही जनसंख्या को कम करने बच्चों का पालन पोषण और माता तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। वैसे यह सर्वविदित है कि एक लड़के की शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति को शिक्षित करना है जबकि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ग्रामीण विकास पर नारी शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आज भी चाहे हम 21वीं सदी में चले जाएं। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा नहीं मिल पाया है। आज भी गांव में लड़की के पैदा होने पर वैसी ही खुशी नहीं मनाई जाती जिस प्रकार लड़का के पैदा होने पर या भेदभाव शिक्षा के साथ–साथ खानपान में भी देखने को मिलता है। लड़की को चिराग मानकर अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है जबकि बालिका को पर कभी–कभी तो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रखा जाता है।

समाज में शिक्षा के महत्व अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। मानव मस्तिष्क एवं आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष घटक है । शिक्षा मानव मस्तिष्क के कार्य करने का ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसमें मनुष्य अपने अच्छे बुरे का सही आकलन कर पाने में संक्षेप हो जाता है तथा समाज में होने वाले शोषण को भी पहचानने एवं उससे बचने में भी सफल होता है। आदिवासी जनसंख्या के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि महिला शोषण की शिकार थी एवं विकास की मुख्यधारा से अलग रही है। इसका मुख्य कारण शिक्षा के अभाव में उनका विकास न होना था। जिले में किसी भी योजना का दोहन नहीं हो पाया इस दृष्टि से विकास की मुख्यधारा से अलग रही है। जिले में कोई भी योजना पूर्ण सफल नहीं हो पाई इसका मुख्य मूल कारण विकास की किसी भी परियोजना यह कार्यक्रम की सफलता के लिए समाज में नारी का शिक्षित होना प्राथमिकता के साथ आवश्यक है।

शोध से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद प्रतिवर्ष छात्राओं की संख्या बढ़ी और आदिवासी छात्राओं में महिलाओं में साक्षरता के प्रति रुझान बढ़ा। यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर इन आदिवासी छात्रों की संख्या अधिक रही लेकिन उच्चतर कक्षा में इनकी संख्या काफी कम थी। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं और माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के बीच एक बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन कार्य छोड़ देती थी। माध्यमिक स्तर के बाद उच्च कक्षाओं तथा माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय तक आते–आते संख्या और भी कम होती गइ। जिले में छात्राओं जिले में छात्राओं में उच्च कक्षा में अध्ययन के प्रति अरुचि एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। अतः शासन का यह दायित्व किस बात का पता लगाएं कि छात्राएं इस कक्षा में आते–आते अध्यापन कार्य क्यों छोड़ देती है ? जीवन स्तर के सुधार तथा आर्थिक विकास का कार्य जब तक अच्छे ढंग से नहीं होगा जब तक उच्च स्तर के अध्यापन के प्रति रुचि नहीं होगी । उन्हें साक्षर नहीं शिक्षित करने की आवश्यकता है । यद्यपि शासन शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं लेकिन क्या यह प्रयास सुविधाएं उन लोगों तक पहुंच पाई है जिन्हें उनकी आवश्यकता है।

यही कारण है कि प्रशासन सही रास्ते को सही दिशा को खोज करने में असमर्थ रहा है अतः यहां प्रयोगिक पूर्ण परिचित प्रत्येक स्तर पर प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता पार्टी के सजग राजनीतिक कार्यकर्ता, साफ–सुथरी नियोजित अर्थव्यवस्था, समर्पित अधिकारी वर्ग और अत्यधिक व्यापक नियोजन की आवश्यकता है, तभी सफलता की आशा की जा सकती है।

सन 1960 में प्रत्येक गांव के बीच एक स्कूल का निर्माण हुआ इसका कार्य क्षेत्र 9.6 मील या पठारी इलाकों में स्कूल का कार्य क्षेत्रफल अधिक या 2/3 से अधिक जनसंख्या छोटे गांव में रहती थी । जिसकी संख्या 500 से कम थी । जिससे कई गांवों में ग्रामीणों के जागरुक ना होने के कारण स्कूल नहीं थे जबकि बड़े गांव में शैक्षणिक व्यवस्था थी।आज भी आदिवासियों के बीच महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जा सकता है । वे अभी तक शिक्षा का मूल्य नहीं पहचान पाए।

	1951	1961	1971
साक्षरता	2.4	3.0	7.86

जिले में शिक्षक क्षेत्र में आश्चर्यजनक बदलाव 1961 के बाद में आया। इसका कारण 1951 से 1961 तक प्राथमिक स्कूलों की संख्या 281 से 543 हो गई। छात्राओं के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि 1951 से 1961 तक 970 से 10000 छात्रों की संख्या हो गई थी, जो कि 10 गुना अधिक थी । प्रयास अवश्य किया गया लेकिन भागीरथ प्रयास 1964 के बाद ही प्रारंभ हो गए। भारत के स्वतंत्र होने के साथ एक आशा की किरण जागी, यह वर्ग धीरे–धीरे उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। नवीन तरीके अपनाए गए जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। जाति धर्म को ताक में रखकर अभिभावकों को प्रोत्साहित किया गया जिससे अपने घर के लड़कियों को भी स्कूल भेजें। इन प्रयासों में से 1950 के बाद आ" चर्यजनक बदलाव आया और स्कूल जाने वाली बालिकाओं के प्रतिशत में वृद्वि हुई।

Literacy Percentage (1951-1991)

Total	1951	1961	1971	1981	1991	Male &Female
Total	8.3	14.2	18.74	22.92	29.89	
Male	14.0	23.4	28.77	34.71	41.79	
Female	2.4	5.0	7.86	11.16	17.85	
Rural	7.30	12.5	16.19	20.24	27.02	
Urban	24.02	48.0	54.71	58.18	64.42	

मंडला जिले में महिलाओं की शिक्षा के स्तर और उसकी परंपरा के बारे में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि जिले के प्रारंभिक काल में शिक्षा का क्या स्वरूप रहा है। शिक्षा के बारे में व्यापक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । पूर्णता पिछड़ा एवं आदिवासी जिला होने के कारण यहां शिक्षा का व्यवस्थित प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया था लेकिन स्वतंत्रता के बाद मिशनरियों के प्रवेश एवं कुछ संस्थानों द्वारा जिले की शैक्षणिक स्तर उठाने का प्रयास किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्त्री जागरूकता के बिना ग्रामीण परिवारों का विकास संभव नहीं है। इसके बिना गांव की तरक्की में अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकते। जहां तक पर्याप्त ग्रामीण महिला साक्षरता से बढ़कर सुशिक्षा से जागरुक नहीं हो जाती, तब तक ग्राम विकास संभव नहीं हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक विकास में महिलाओं की

भूमिका नगण्य है।इसका कारण महिलाओं का शिक्षित होना है। ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि गांव में पुरुष वर्ग ज्यादातर घर के बाहर रहता है तथा बच्चों के पालन–पोषण का दायित्व महिलाओं पर ही होता है। महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण घर के बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए गांव में आज शिक्षा का प्रतिशत अत्यंत कम है। कुछ कक्षाओं की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों का प्रतिशत अधिक है। विशेष रूप से 90 प्रतिशत बालिका प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के ऊपर अध्ययन नहीं कर पाती। महिलाओं का शिक्षित होना सामाजिक कुरीतिया, अंधविश्वास, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक आवश्यक है। अशिक्षित और सामाजिक रुप से कमजोर होने के कारण ग्रामीण महिला श्रमिक शोषण का सबसे अधिक शिकार होती है। उन्हें अपने कठोर परिश्रम का मूल्य प्राप्त भी नहीं होता जो पुरुष और शिक्षित श्रमिकों को प्राप्त होता है।

गांव में लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति की जगह घरेलू कामकाज में लगाए जाना भी एक बाधा है। गांव में घरेलू कामकाज बाल मजदूरी से कम नहीं है। इसके आर्थिक लाभ के चलते ग्रामीण अभिभावक अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते। जो शुरू में भेजते हैं वे बाद में रोक देते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि एक बालिका ससुराल जाने से अपने परिवार को ₹60000 के बराबर का लाभ पहुंचाती है। ऐसे में कोई गरीब मां बाप अपने बच्चे को पढ़ाई में लगाने की भूल कैसे कर सकते हैं।

वास्तव में शिक्षा के बहुआयामी लाभ और लाभप्रद प्रभाव को ध्यान में रखकर ग्रामीण जीवन में इसी वरदान के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। यही ग्रामीणों को अज्ञान और अंधविश्वास से निजात दिला कर उनमें नई चेतना का संचार करती है। जिससे ग्रामीण विशेषकर महिलाओं में अधिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना का उदय होता है।

योंग में जीवन का महत्व

डॉ. एल.जे. पचौरी
पूर्व विभागाध्यक्ष योंग एवं प्रकृति चिकित्सक, शा. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, भोपाल

मानव जीवन अमूल्य है यह बड़े ही शुभ कर्मों के पुण्य का परिणाम है। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि यह मानव शरीर दैव लोकवासियों के लिये दुर्लभ है तथा यह परमात्मा की दया से ही प्राप्त होता है। जीव का मूल स्वरूप आत्म साक्षात्कार है। जिस के दो मार्ग हैं। एक उपासना मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। इन दोनों में से जीव एक मार्ग का अनुशरण कर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकता है लेकिन कोई अवधि निश्चित नहीं है। यह उपाय रूप है। भगवान ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव और श्रीमद्भगवतगीता में प्रभु ने कहा कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम् शरणम् वृज अर्थात इन परमात्मा के वाक्यों की वास्तविकता यह है कि आप मानव अपने हृदय में तथा कर्म में किसी यक्ष, गदर्व, प्रेत, भूत, राक्षस इत्यादि में से किसी का न पूजन करें और न ही स्मरण करो। तुम जिसको भजोगे उसी को प्राप्त होओगे इसलिए मन में दृढ़ निश्चय कर निर्मल अवस्था को धारण कर अर्थात निष्काम करते हुए मेरी शरण में आजा तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्ह्चर्य, अपरिग्रह महावृतों का दृढ़तापूर्वक अनुशरण करता हूँ और साथ ही पवित्रता के भाव की दृढ़ता के साथ ही सदा हर हाल मैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में संतोष की स्थिरता हो शरीर को ऋतुअनुसार योगाग्नि में तपाकर मकरहित अवस्था के निर्माण की स्थिति बनाये रखनी है। साथ ही आत्म चिंतन की निरंतरता से लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सदैव सजग रहना ऐसे भाव की नित निर्मल भावना जगाए रखना साथ ही मानव के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह मन, वचन व कर्म से परमात्मा को समर्पित हो जाए और साधना के माध्यम से नित नवीनता का अवलोकन करे जीवन धन्य रूपी साधना का कहा जाता हैं जो धर्म के लिये शरीर धारण करता है। उसे प्रति पल सत्य की राह दिखती हो और परोपकार ही उसकी जिज्ञासा हो जीवन का प्रत्येक क्षण सत्संग में जाए जिससे स्वयं की व सानिध्य प्राप्तजनों की गति श्रेष्ठ हो। जीवन में सुख, संतोष बनाए रखकर कामनाहीन जीवन के प्रवाह का उठायें क्योंकि मानव की तीन प्रमुख कामेन्द्रियाँ हैं और इन तीनों का आपसी सामंजस्य अति आवश्यक है। अर्थात जो मन में भाव उत्पन्न हो वही वाणी के माध्यम से बाहर आये और शारीरिकता के माध्यम से उसे सम्पन्नता प्राप्त हो। यदि इन तीनों में एक रूपता का अभाव है तब निश्चित ही असात्म का उदय होकर मानसिक द्वन्द्व में वृद्धि होगी और संतुलन नष्ट हो जाएगा। मन को प्रधान कामेन्द्रिय माना गया है। इस का विषय सोच विचार चिंतन है। वाणी मनुष्य का भूषण है जिसके द्वारा मनुष्य सुख दुःख का वरण करता है। शरीर के अंगों के माध्यम से सम्यक कर्म करना ही उचित है। हमारे ऋषियों ने जीवन के चार आश्रम निर्मित किये हैं– ब्रम्ह्चर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मानव वैदिक विधान का पालन कर ब्रम्ह्चर्य संयम से मानव ऊर्जा के भण्डार का संग्रह कर जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है संचयी ऊर्जा का प्रसन्नतापूर्वक व्यय कर यश कमाता है और कल्याणकारी कार्यों को करता हुआ यशस्वी होकर यौगिक मार्ग का अनुशरण कर वंश की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ इस आश्रम से निवृति पाकर परिवार, देश, जाति के मार्गदर्शक रूप में मोह का त्यागकर वानप्रस्थ आश्रम का निर्वहन करता हुआ जीवन के अन्तिम आश्रम सन्यास का वरणकर हरि ऊँ नारायण के दर्शन प्रत्येक पदार्थ के कण में करने लगता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरूषार्थों का भरपूर उपयोग कर अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना ही जीवन का परम सत्य है तथा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन के महत्व को समझते हैं।

स्वास्थ्य का सामान्य ज्ञान :– स्वास्थ्य मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने स्वस्थ उसे माना जिसके दोष, धातु, मन समअवस्था में रहे ऐसे मानव की आत्मा मन इन्द्रियां सदैव प्रसन्न रहती हैं। अर्थात जो निरोगी हैं। लेकिन इस की प्राप्ति उत्तम आचरण वाले को प्राप्त होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यवहार स्वयं को बुरा

लगता हो वह दूसरों के प्रति कदापि नहीं अपनाना चाहिए ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति सदाचारी होता है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा समृद्ध रहता है। शरीर, मन, वाणी से किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए और न ही घृणा करनी चाहिए। माता–पिता व गुरूजनों की सदैव आज्ञा पालन करते हुए सेवा करनी चाहिए साथ ही अशुभ चाहने वालों की भी आपत्ति में सहायता करनी चाहिए। प्रतिकूल व अनुकूल स्थिति में सहजवृति युक्त रहना चाहिए। आवश्यक कार्य को मन लगाकर समय पर करना एवं मादक दृश्यों से अलग रहना इनका विचार तक न करना सदा उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार, निद्रा एवं मैथुन ये तीनों की आवश्यकता रहती है तथा आचार के अधीन प्रातः निद्रा त्याग कर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर उचित बाल भास्कर का अभिवादन करना चाहिए। सूर्य उदय के चार घड़ी पूर्व के समय को हमारे पूर्वजों ने ब्रह्ममुहूर्त अर्थात सबसे उत्तम समय माना है। प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले पशु–पक्षी नवजात शिशु निद्रा का त्यागकर चंचल होने से यह सिद्ध है कि निरोगी रहने के लिए यह उत्तम समय है और इस के सकारात्मक परिणाम स्वास्थ्य प्राप्त कर अनुभव प्राप्त किये जा सकते हैं। चेहरे पर तेज शरीर अतिरिक्त ऊर्जावान और मन अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। प्रातः की बेला में ठण्डा जलपान करना चाहिए। ठण्डे जलपान को यदि नासिका के माध्यम से ग्रहण किया जाये तब बुद्धि में प्रखरता, नेत्र ज्योति वृद्धि और असमय हुए स्वेत वाला पुनः काले होने लगते हैं एवं असमय शरीर में झुर्रियां न पड़कर साधक सदैव यौवनानुभूति करता है। जलपान कर शौचादि क्रिया करना चाहिए तथा इस के पश्चात उत्तम स्वास्थ्य के लिए भ्रमण भी आवश्यक है। इससे प्रातः की शुद्ध वायु का सेवन श्वसन मार्ग के अलावा शरीर के रोम कूपों के माध्यम से शरीर को मिलता है। इसके बाद प्रकृति द्वारा अनुमोदित फल तथा उनका रस, जूस या जीवित अल्प मात्रा में आहार लेना चाहिए। पश्चात आवंटित श्रम करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए श्रम उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए आहार और उतनी ही आवश्यक स्वच्छता है। फिर चाहे वह शरीर से सम्बन्धित हो या स्थान से सम्बन्धित हो या मन बुद्धि चित्त से सम्बन्धित हो। स्वस्थ मनुष्य की निधि है और इस को प्राप्त कर वह अपने जीवन के सम्पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील रहता है। हमेशा मनुष्य सुख की कामना करता है और स्वास्थ्य से सुख की प्राप्ति संभव है। लोकोक्ति भी है–''पहला सुख है निरोगी काया'' क्योंकि रोगी व्यक्ति न ही रसों का स्वादन कर सकता है और न ही उसे इन्द्रिय सुख की प्राप्ति ही होती है और न ही चारों पुरूषार्थों में से एक की भी प्राप्ति वह कर सकता है अर्थात कामनाहीन जीवन यापन करता है और अस्वस्थ मनुष्य को मोक्ष भी नहीं मिलता है जबकि मनुष्य जीवन भर स्वास्थ्य की कामना तो करता है पर आचरण नहीं करता। जबकि निरोगी शरीर की प्राप्ति हेतु इच्छा रखता है। ऐसे मनुष्यों को स्वास्थ्य संरक्षण व संवर्धन का ज्ञान होना आवश्यक है। जिनमें स्वास्थ्य के निर्धारण तत्वों का ज्ञान रोगों की जानकारी रोगों के कारण तथा उनके शरीर पर दिखने वाले लक्षण तथा उपचारित तत्वों का सामान्य ज्ञान यह सत्य है कि मनुष्य को आहारीय पदार्थों का ज्ञान उसे तैयार करने का समय स्थान तथा आहारीय पदार्थों को ग्रहण करने का तरीका व मात्रा तथा हम के साथ आहारीय प्रणाली का सामान्य ज्ञान और उन अंगों द्वारा पाचन में सहयोग की जानकारी महसूस करना। आहार के पाचन में व्यवस्था और अव्यवस्था का ज्ञान वरूण ऋतु अनुसार आहार का ज्ञान विहार की व्यवस्था का ज्ञान होने से ही मानव स्वस्थ रह सकता है। पक्षियों की आहार ही औषधि है। इस ज्ञान की विद्यार्थी सामान्य जन साधक, शिक्षक।

जीवनचर्या :– मानव जीवन अमूल्य है। इसे प्राप्त कर व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस जीवन का अर्थ ही यह है कि आप कौन हैं? यहां क्यों आये हैं? इसका उद्देश्य क्या है इसे जानना है और इसे जानने के लिए ऋषियों के निर्मित मार्ग पर चलना होगा। जीवनचर्या की सार्थकता के लिए शारीरिक व मानसिक तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वच्छता को अपनाना अति आवश्यक है। जिस तरह योजन विश्राम ब्रम्हचर्य यह त्रय स्तम्भों से स्वास्थ्य लाभ होता है। लेकिन उसकी परिपुष्टता के लिए व्यायाम भी आवश्यक है। साथ ही स्वच्छता के नियमों के पालन से उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए स्वास्थ्य साधनों में स्वच्छता का अपरिहार्य महत्व है। इसलिए मानव को स्वच्छता अपने अधिक से अधिक व्यवहार में लाना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। ऋषियों का कहना था कि समस्त कलेशों की मूल प्रसापराध है और यह प्रशापवाध मानसिक अस्वस्थता की वजह से ही होता है। क्योंकि मन के स्वस्थ रहने से बुद्धि में विकृति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। चित्त का दोष रहित होना ही मानसिक स्वस्थता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य आदि विकारों से मन विकृत न हो और ऐसा होने से मनुष्य चरित्र का धनी

आदर्शवान प्रतिष्ठित सम्पन्न और जीवन की हर दशा में यशस्वी होता है। मानसिक स्वस्थता के लिए हमारे समाज के प्राचीन विधान जैसे संध्या वंदन, अग्निहोत्र, ध्यान, जप, साधना, स्वाध्याय आदि क्रियाओं से मानसिक स्वच्छता के साथ ही मनःस्थिति दृढ़ होती है। संध्या वंदन करने से मनुष्य का मानसिक विश्वास जागृत होता है। साथ ही धैर्य एवं संयम की भावना का उदय होता है और अग्निहोत्र के वातावरण में स्वच्छता आती है। अर्थात वह शुद्ध होता है।

संदर्भित ग्रंथ :–

रामचरित मानस	–	गीता प्रेस, गोरखपुर
हठ प्रदोषिका	–	स्वा0 सत्यानन्द
घेरेण्य संहिता	–	स्वा0 निरंजनानन्द
यजुर्वेद	–	गायत्री शक्ति पीठ हरिद्वार
भारतीय दर्शन	–	प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा

ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) का कृषि पर प्रभाव

रामअवध सिंह यादव
डॉ0 उमारतन यादव एसोसिएट प्रोफेसर, बुन्देलखण्ड डिग्री कॉलेज झाँसी (U.P.)

प्रस्तावना : ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान में हुई वृद्धि से है। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी और इसके वायुमण्डल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान में इसी वृद्धि को 'ग्लोबल वार्मिंग ' की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद् 'वालेस ब्रोएकर ' ने 1970 के दशक में प्रदान किया था।

ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें तथा पर्यावरण प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैसें (जैसे – कार्बनडाई आक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मिथेन, नाइट्रस आक्साइड तथा ओजोन) पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा को अनन्त वायुमण्डल में जाने से रोके रखती है जिसके कारण वायुमण्डल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्वप्रमुख गैस 'कार्बन डाइ आक्साइड' है। 1880 से पूर्व वायुमण्डल में CO_2 की मात्रा 280 PPM थी जो आज आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार 379ppm हो गई है। CO_2 की वार्षिक वृद्धि दर गत वर्षों में (1995–2009) 1.9ppm वार्षिक है। आईपीसीसी ने भविष्यवाणी की है कि सन् 2100 आते–आते इसके तापमान में 1.1 से 6.4^{0}C तक बढ़ोत्तरी हो सकती है। सदी के अंत तक समुद्री जल–स्तर में 18 से 58 सेमी. तक वृद्धि की सम्भावना है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा, कहीं लू तो कहीं ठंड, कही बर्फ की चट्टानें टूट रहीं है तो कही समुद्री जल–स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही हैं। आज जिस गति से ग्लेसियर पिघल रहे हैं। इससे भारत और पड़ोसी देशों को खतरा बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से फसल चक्र भी अनियमित हो जायेगा, इससे कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होगी। मनुष्यों के साथ–साथ पशु–पक्षी भी इस प्रदूषण का शिकार हो रहें हैं। ग्लोबल वार्मिंग पक्षियों के दैनिक क्रिया–कलाप और जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यदि वर्तमान गति से पर्यावरण प्रदूषण जारी रहा तो आने वाले 75 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 03 – 06^{0}C की वृद्धि हो सकती है। जिससे बर्फ के पिघलने से समुद्री जलस्तर में 1 से 1.2 फीट तक की वृद्धि हो सकती है और मुम्बई, न्यूयार्क, पेरिस , लन्दन, मालदीव , हालैण्ड और बांग्लादेश जैसे देशों के अधिकांश भू–खण्ड समुद्र में जलमग्न हो सकते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई है कि समस्त विश्व के पास ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने के लिए मात्र 10 वर्ष का समय और है। यदि ऐसा नहीं होता है। तो समस्त विश्व को इसका परिणाम भुगतान पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को 21 वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्वयुद्ध या किसी क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉइड) के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है।

क्यों पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्याः–

ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में 18 वीं सदी की औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। इसका श्री गणेश 18 वीं सदी के अंत में यूरोप से हुआ था। 19 वी सदी के पूर्वार्द्ध में यह पूर्वी यूरोप से लेकर अमेरिका तक तेजी से फैल गया था। औद्योगीकरण की प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन के लगातार प्रयोग से वातावरण में कार्बन–डाइ–आक्सॉइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती गयी। इसका सीधा परिणाम पृथ्वी की गर्माहट के रूप में आज हमारे सामने है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में पिछली शताब्दी की अपेक्षा इस शताब्दी में 1.5^{o}C तक की वृद्धि हुई है। एक अन्य अनुमान के अनुसार वर्ष 2080 तक पृथ्वी के तापमान में 1 से 3.5 ^{o}C तक की वृद्धि की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना कोई बड़ी घटना नहीं है किन्तु ताप वृद्धि के साथ–साथ वातावरण में कार्बन–डाई–ऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि होना अधिक हानिकारण है। गैसों की इस वृद्धि से ही आज जलवायु में परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि यही स्थिति रही तो आगामी 100 वर्षो में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र के जलस्तर में 19 सेमी. से लेकर 95 सेमी. तक की वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम काफी भयावह हो सकते है।

आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक ग्लोबल वार्मिंग कोई समस्या नही थी। वर्ष 1861 में पहली बार वैज्ञानिक टिडेल ने यह तथ्य उजागर किया कि

वायुमण्डल में जल वाष्प, कार्बनडाईआक्साइड, लम्बे तरंग दैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर लेते है जिससे वातावरण अधिक गर्म हो जाता है। इसी क्रम में 1896 में स्वीडिश वैज्ञानिक आरहीनियस ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि कोयले के दहन से कार्बनडाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है तथा पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। 1924 में अमेरिका के भौतिक विज्ञानी 'लोटका' ने अपने अध्ययन द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण आगामी 500 वर्षों में पृथ्वी के वातावरण में कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा वर्तमान स्तर से दोगुनी हो जायेगी। 1949 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बताया कि 1850 से 1940 के मध्य वातावरण में कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा में 10% तक की वृद्धि हुई है।

तालिका नं. 1
प्रमुख ग्रीन हाउस गैंस उत्सर्जक देश

क्रमांक	देश	ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (प्रतिशत में)
1	चीन	20.09
2	अमेरिका	17.89
3	रूस	7.53
4	भारत	4.10
5	जापान	3.79
6	जर्मनी	2.56
7	ब्राजील	2.48
8	कनाडा	1.95
9	द.कोरिया	1.85
10	मैक्सिको	1.70

स्त्रोत – EU EDGAR DATABASE

कृषि पर प्रभाव : वर्तमान विश्व के बढ़ते औद्योगीकरण एवं वाहनों की संख्या से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इजाफा हुआ है। बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2016 अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रिकार्ड किया गया है। गर्माती धरती का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। भारत के संदर्भ में यह चेतावनी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में दिसम्बर, 2009 में आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल क्लोइमेट रिस्क इन्डेक्स 2010 द्वारा जारी सूची में भारत उन प्रथम 10 देशों में है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

एक अध्ययन के अनुसार, सन् 2050 तक शीतकाल का तापमान लगभग 3 से 4 ^{o}C तक बढ़ सकता है। इससे मानसूनी वर्षा में 10 से 20 प्रतिशत तक कमी होने का अनुमान है। वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होने से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु में होने वाला परिवर्तन हमारी राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा पिछले 5 सालों में 2 प्रतिशत तक कम हुआ है। 2009 का वर्ष हमारे लिए चेतावनी भरा वर्ष रहा है। इस वर्ष 23 से 25 प्रतिशत तक वर्षा कम हुई। जिससे देश के बहुत से भागों में खड़ी फसले सूख गई जिससे न केवल खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ बल्कि उनकी कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई।

कोपेनहेग में आयोजित सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कहा कि इससे लगभग 64% लोगों पर प्रभाव पड़ेगा जिनके जीवनयापन का साधन कृषि है और सबसे बड़ा डर खाद्य सुरक्षा को लेकर है। कृषि एवं जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है जिनकी

कुल आय का लगभग 60% हिस्सा अन्न, जल एवं स्वास्थ्य संबंधित मदों पर खर्च होता है। ऐसा अनुमान है कि सूखे के कारण खरीफ के मुख्य फसलों चावल व दलहन तथा तिलहन में 20% तक कमी हो सकती है। देश के खाद्यान्नों में 5 प्रतिशत कमी की संभावना G.D.P. को एक प्रतिशत तक प्रभावित करेगी। प्रो. स्वामीनाथन ने कहा है कि तापमान में $10^{O}C$ की वृद्धि से भारत में 70 लाखटन गेहूँ के उत्पादन में कमी आयेगी। एक अध्ययन के अनुसार यदि तापमान में 1 से 4 ^{O}C तक वृद्धि होती है तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। भारत में चावल के उत्पादन में तापमान बढ़ने से 2020 तक 5 से 6 प्रतिशत, आलू के उत्पादन में 2020 तक तीन प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। जबकि जनसंख्या बढ़ने से सभी खाद्य पदार्थो की मांग में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप खाद्य संकट हमारे सामने एक भयंकर समस्या होगी। जलवायु परिवर्तन से न केवल फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होगी बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फल एवं सब्जियों वाली फसलों में फूल तो खिलेंगे लेकिन उसके फल या तो बहुत कम बनेगें या उनकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। तापमान वृद्धि से समूक्त्व का जल स्तर बढ़ जायेगा जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। जल स्तर बढ़ने से लोगों के खेतों एवं घरों को समुद्र निगल जायेगा, भूमि लवणीय हो जायेगी और कृषि क्षेत्र में कमी होगी। तापमान बढ़ने से हिमनद तेजी से द्रवीभूत होंगे, वर्षा एवं जलवायु के पैटर्न मे तेजी से बदलाव आयेगा, जिसका प्रभाव कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर पड़ना स्वाभावितक है।

तालिका न0 2

जलवायु परिवर्तन के आगामी वर्षो में होने वाली तापमान वृद्धि एवं वर्षा में परिवर्तन के अनुमान का विवरण

वर्षा	मौसम	तापमान वृद्धि डिग्री. से.		वर्षा में परिवर्तन प्रतिशत	
		न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम
2020	रबी	1.08	1.54	–1.95	4.36
	खरीफ	0.87	1.12	1.81	5.10
2050	रबी	2.54	3.18	–9.22	3.82
	खरीफ	1.81	2.37	7.18	10.52
2080	रबी	4.14	6.31	–24.83	4.50
	खरीफ	2.91	4.62	10.10	15.18

स्त्रोतः– EU Edgar database

तालिका न0 2 का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि आगामी वर्षो में पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होगी जिसका प्रभाव कृषि के प्रत्येक भागों पर पड़ना स्वाभाविक है।

1. फसलों पर प्रभावः– अध्ययनों के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रत्येक 10 ^{O}C तापमान बढ़ने पर गेंहू का उत्पादन 4–5 करोड़ टन कम होता जायेगा। इसी प्रकार 20 ^{O}C तापमान बढ़ने से धान का उत्पादन 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जायेगा, जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता ही प्रभावित नही होगी वरन् उसकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अनाज में पोषक तत्वों एवं प्रोटीन की कमी होगी जिसके कारण संतुलित भोजन लेने पर भी मनुष्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

2. मिट्टी पर प्रभावः– तापमान बढ़ने से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मृदा में लवणता बढ़ेगी, जैव विविधता घटेगीं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारम्बारता बढ़ने से मृदा का क्षरण होगा। वहीं दूसरी ओर सूखा के कारण भूमि बंजर होती जायेगी।

3. कीट एवं रोगों पर प्रभावः– जलवायु परिवर्तन होने से कीट व रोगों की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि गर्म जलवायु कीट–पतंगों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। कीटों एवं रोगों में वृद्धि के साथ ही उनके नियंत्रण हेतु अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जायेगा जो

जानवरों व मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा।

4. जल संसाधनों पर प्रभावः– ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक प्रभाव जल के स्त्रोतों पर पड़ेगा। जल उपलब्धता की भयंकर समस्या उत्पन्न होगी तथा सूखे एवं बाढ़ की बारम्बारता में वृद्धि होगी। अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क मौसम अधिक लम्बा होगा जिससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्षा की अनिश्चितता भी फसलों के उत्पादन को प्रभावित करेगी तथा जल स्त्रोतों के अत्यधिक दोहन से जल स्त्रोतों पर संकट के बादल मंडराने लगेगे। अधिक तापमान और वर्षा की कमी से सिंचाई हेतु भू–जल संसाधनों का अधिक दोहन किया जायेगा। जिससे धीरे–धीरे भू–जल इतना ज्यादा नीचे चला जायेगा कि उसका दोहन करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी सिद्ध होगा। उदाहरण–के तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों के कुछ भागों में भू–जल स्तर क्रिटिकल प्वाइंट तक पहुँच गया है।

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल :

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन – द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएँ प्रारम्भ हुई। 1972 में स्वीटन की राजधानी स्टॉक होम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तय हुआ कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनायेगा, इस आशय की पुष्टि हेतु 1972 में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया तथा नौरोबी को इसका मुख्यालय बनाया गया। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस' घोषित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया।

वियना सभा–ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में वियना (आस्ट्रिया) में वियना कन्वैशन हुई थी, जो ओजोन क्षरण पदार्थो (ODS) पर सम्पन्न प्रथम सार्थक प्रयास था। पुनः 1995 में सम्पन्न वियना सभा में ओजोन रिक्तिकारक पदार्थों पर एक समझौता हुआ। इस सभा में ओजोन परत के बढ़ते रिक्तिकरण को कम करने के लिए तीन 'ओ.डी.एस.' पदार्थों 'सी.एफ.सी.' , एच.सी. एफ.सी. और मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती पर शर्तें तय की गयी।

मॉट्रियल समझौता (1987) :

यह प्रोटोकॉल, ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गयी है, जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यह संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितम्बर 1987 को खोला गया था और 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हो गयी, जिसके बाद इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी , में हुई। ओजोन परत के क्षय को रोकने वाले, ओजोन अनुकूल उत्पादों और जागरूकता बढ़ाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषयों के कार्यान्वयन के महत्व का उल्लेख करते हुए ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) :–

स्टॉकहोम सम्मेलन की 20 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी, रियो–डी–जेनेरिओ में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे 'अर्थ सम्मिट (EARTH SUMMIT) या 'प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन' भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने 'टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना' एजेंडा 21' स्वीकार किया। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। 'रियो–डि–जेनेरियो' में यह निर्धारित किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होगे। तथा जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्यक्रमों पर चर्चा करेगें। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कोप) की संज्ञा प्रदान किया गया। वर्ष 1995 में पहला 'कोप सम्मेलन' आयोजित किया गया। वर्ष 1995 से 2017 तक कुल 23 कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज (कोप) आयोजित किये गये।

रियो 20 घोषण पत्रः द फ्यूचर वी वांट :

'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन ''रियो20' का आयोजन ब्राजील के रियो–डी–जेनेरियों में 20–22 जून 2012 को आयोजित हुआ। चूंकि इस सम्मेलन का आयोजन रियो में वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद किया गया था, इस लिए इसका नाम 'रियो20 ' रखा गया था। रियो20 सम्मेलन के बाद विश्व के नेताओं द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की गई जिसे 'द फ्यूचर वी वांट' नामक शीर्षक से जारी किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख नेता दो महत्वपूर्ण मांगों पर सहमत हुए। उनमें से

एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जबकि दूसरा वित्त से जुड़ा हुआ है। यह रियों सम्मेलन में भारत की सफलता के रूप में देखा गया, क्योंकि ये दोनों प्रस्ताव भारतीय थे तथा इसे समूह 77 देशों का जोरदार समर्थन मिला।

क्योटो प्रोटोकॉलः–

संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में 'यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) अस्तित्व में आय। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। इसके अंतरगत विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। प्रोटोकॉल के अनुसार विकसित देशों को 6 ग्रीन हाउस 'गैसो (CO_2, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन व परफ्लूरोकार्बन) के उत्सर्जन में कम से कम 5 प्रतिशत की कमी करनी होगी। भारत ने अगस्त 2002 में क्यूटों प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये और उसका अनुमोदन किया। इस प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को शर्तों में कुछ छूट दी गई है जिससे भारत को ग्रीन टेक्नोलॉजी हस्तांतरण एवं विदेशी निवेश तथा कार्बन व्यापार के क्षेत्र में फायदा हो सकता है।

जोहांसबर्ग पृथ्वी सम्मेलन :

सितम्बर, 2002 में जोहांसबर्ग (दक्षिणी अफ्रीका) में, दूसरे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से चर्चित सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में 1992 में रियो–डी–जेनेरों में हुए पृथ्वी सम्मेलन में लिए गये निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की गयी।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनः–

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कटौती के मामले में विश्वव्यापी सहमति कायम करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान मे वैश्विक सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली द्वीप में नासा दुआ (NASA DUA) में 13–14 दिसम्बर , 2007 को सम्पन्न हुआ।

23 वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बॉन में संपन्न (COP–23) :

6–17 नवम्बर 2017 के मध्य जर्मनी के बॉन शहर में यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के 23 वें सम्मेलन (COP–23) का आयोजन हुआ।

सम्मेलन से संबंधित अन्य तथ्य–

1– यह सम्मेलन वर्ष 1992 के रियो सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन) के बाद 23 वां (COP–23) तथा 2015 के पेरिस समझौते के बाद का द्वितीय भाग था।

2– सम्मेलन का मुख्य विषय 2020 तक जलवायु वित्त पोषण हेतु 100 बिलियन डॉलर का अनुदान देने का वादा एवं क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को पर्याप्त देशों द्वारा स्वाकार नही किया जाना था।

3– अमीर देशों (विकसित देशो) द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धताओं, कार्यवाइयो, वित्तीय सहायता, विभेदीकरण, नुकसान एवं क्षति से संबंधित मुद्दे कॉप–23 सम्मेलन के मुख्य मुद्दे थे।

4– सम्मेलन में कोयले के उत्सर्जन से कार्बन स्पेस पर कब्जा कर चुके विकसित देशों द्वारा गरीब एवं विकासशीन देशों को सहायता देने, का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कार्बन स्पेस जलवायु परिवर्तन पर अंतर –सरकारी पैनल के पांचवे आंकलन में निर्धारित उत्सर्जन का एक मानक है। जिसके तहत वर्तमान में वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के तापमान के मुकाबले 2% या इससे कम होना चाहिए।

कॉप –23 की कमियां :

- अमेरिका का पेरिस समझौते से दूर रहना।
- ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वर्ष 2017 में हुई की वृद्धि जो अब तक कुछ स्थिर स्थिायी दे रही है।
- चीन का कार्बन उत्सर्जन पर ढुलमुल रवैया।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally determined contribution : NDC) को पूरा करने हेतु विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा मजबूत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता पर सहमति न बन पाना।

ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय –

वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से सी.एफ. सी. गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज , एअर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसे मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे सी.एफ.सी. गैसे कम निकलती है।

औद्यागिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ हानिकारक है और इससे निकलने वाला कार्बनडाई ऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होगे। वाहनों से निकलने वाले धुएँ का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपयों पर ध्यान देना होगा यानि अगर कोयले से बनेने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाय तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है तथा साथ ही साथ जंगलों में आग लगने पर रोक लगानी होगी। चूंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार सभी है तथा आपदाएं सभी को प्रभावित करेंगी, इसलिए सम्पूर्ण पृथ्वी की सुरक्षा हेतु विकसित देशों को अपने व्यक्तिगत लाभ–हानि की जगह मानवीय एवं नैतिकता का परिचय देते हुए विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया कराना चाहिए तथा सभी देशों को मिलकर इस वैश्विक समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

संदर्भ सूची –

- ✓ वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- ✓ योजना पत्रिका (2017–18)
- ✓ कुरूक्षेत्र पत्रिका (2017–18)
- ✓ India water portal
- ✓ Wikipedia
- ✓ Hindi-indiawaterportal-org
- ✓ https%//hi-m-wilipedia-org
- ✓ www-deepawali-co-in
- ✓ www-bbc-com
- ✓ khabar-ndtv-com
- ✓ shouttermouth-com
- ✓ प्रतियोगिता मासिका पत्रिका
- ✓ क्रानिकल मासिक पत्रिका
- ✓ घटना चक्र मासिक पत्रिका
- ✓ दैनिक जागरण समाचार पत्र
- ✓ हिन्दुस्तान समाचार पत्र

Bio-Fuel and clean Development Mechanism

Dr. Archana Muthye
Assistant Professor, GS College of Commerce and Economics, Jabalpur

As the population is increasing the economy is also growing, fossil fuels resources are limited.

In the market economy the price of energy supply such as Oil gas or Electricity is driven by the principle of demand and supply which can cause sudden change in price of energy, however in some cases the crisis might be influenced by the lack of free market.

Oil supply is largely controlled by the national Oil Companies of the Nation. World is heading towards a global Energy crisis due to a decline in the availability of cheap oil and recommendations to a decreasing dependency on fossil fuel. The reserves of fossil fuels are very limited and will last only for few years. From the last few decades the search of alternative sources of energy is being carried out by the scientists. The biggest environmental Story of last several years has been energy security and climate change. The main sources of renewable energy are as follow:

- Wind Energy
- Solar Energy
- Bio Diesel

As wind energy and Solar Energy have certain limitations, biodiesel energy has tremendous potential in India. Biodiesel is a renewable fuel made by chemical reaction of alcohol and vegetable oil or animal fat through the refinery process called Trans-esterification. Biodiesel can be used in any diesel engine in pure form or in blended form.

According to Kyoto Protocol all developing Nations have committed collectively to cut down their emission. Biodiesel cut down on targeted emission. Biodiesel used in 20-80 and a catalytic converter will cut air pollution by diesel operation in conventional engine.

No engine modifications are required and biodiesel maintains the payload capacity and range of diesel. Biodiesel is user friendly and the use of the biodiesel blend results in a noticeable change in exhaust odors, Since the biodiesel is oxygenated diesel engine have more complete combustion than petroleum fuel. The jatropha plant serves as a potential oil seed plant in India. It can be grown anywhere in all types of soil. The major oil seed plant jatropha is easier to grow. Jatropha is a Shrub and the plants grow to height of 8 to 10 feet and the life span is 40 years and it is not graced by cattle and can survive in extreme environment.

Benefits from Biodiesel Plants :

- Optimum Utilization of land
- Employment generation in targeted area
- Revenue generation through CDM

Climate change or global warming is one of the global environmental challenges of our time. the emission of greenhouse gases have contributed to climate change such as rising Global temperature, rising sea levels and extreme weather for Clean development mechanism we have to cut down the Carbon Emission.

CDM and Biofuel :

The Clean Development Mechanism is one of the three flexibility mechanisms under the Kyoto Protocol that regulate carbon trading. Under the Kyoto Protocol, countries have committed themselves to a reduction of greenhouse gas emissions.

The Clean Development Mechanism has two objectives: reducing carbon emissions and sustainable development through technology transfer. CDM allows industrialized countries to offset their excess carbon emissions by investing in

clean technology development in developing countries.

In order to calculate the project's emission reductions, a project has to adhere to a specific "methodology", which in CDM terminology refers to a set of rules and formulas on how to calculate the greenhouse gas emission reductions,

A carbon credit is a financial unit used to measure the reduction of greenhouse gas emissions (1 CER = 1 ton CO_2 reduction). CERs are generated through the implementation of clean technology projects in developing countries that reduce greenhouse gas emissions.

Growth in the use of liquid fossil fuels has led to substantial increases of CO2 emission. The international community has put in place measures to reduce gas emissions.

Establishing bio fuel plantations like Jatropha on degraded soils can be a feasible strategy provided that these soils are adequately suffering with specific problems (e.g., nutrient and water imbalance, , shallow rooting depth, drought stress, salinization, crusting) .

Bio-Fuel Production and Wasteland Development :

Ministry of Environment and Forests, Government of India described wasteland as, "degraded land which can be brought under vegetative cover, with little effort, and which is currently under-utilized, and land which is deteriorating for lack of appropriate water and soil management or on account of natural causes". Wastelands are those areas where production of biomass is less than optimum productivity. These lands are economically unproductive and logically unstable. The life supporting systems are under tremendous pressure. Waste land includes such type of land mass which cannot be used for agriculture and other cultivation practices. It amounts to (30-35) per cent of total landmass of India. The most .important natural resource, upon which all human activity is based since time immemorial, is land. However, considerably damages our land resource base. Further, land also suffers from various kinds of soil erosion, degradation and forestation. In India, there is an urgent need to reverse this trend and restore the wastelands to their production potential in order to meet the demands of increasing population and other developmental activities. The ministry of rural development had introduced a special scheme in 1994-95 offering grants and subsidies to all the parties involved landowners, farmers, corporate and financial institutions for the development of wasteland. Due to poor response, the scheme was discontinued in 2004.

Conclusion :

The promotion of biofuels as a clean fuel alternative has been a significant aspect of the global quest for clean development. However, the challenges of problematic food security and environmental concerns can not be overlooked

The Clean Development Mechanism is a very important part of producing biodiesel. It is applicable, to all stages of the production and utilization. The benefits, via tradable Carbon Credits, can be given to all the contributors to the effort of production as well as the users of biodiesel.

References :

[1] Energy Information Administration (EIA): Anural Energy Outlook 2006 – with projections to 2030. US Department of Energy, February 2006.

[2] http://www.mdpi.com